



अनुष्का शर्मा को बीएमसी ने थमाया नोटिस

>>7

दैनिक जागरण

न्यूज गैलरी

सिटी न्यूज ▶ पृष्ठ 2

एमबीवीएस छात्रों से रैगिंग, जबरदस्ती पिलाई शराब

नई दिल्ली : जीटीबी अस्पताल स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में एमबीबीएस के छात्रों के साथ रैगिंग, जबरन शराब पिलाने और जातिसूचक शब्द इस्तेमाल करने के मामले से हड़कंप है। जिन दो छात्रों ने यह शिकायत की है, उनमें एक दलित है। कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पर कांग्रेस का हंगामा

नई दिल्ली : अपने मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई तेज होने से कांग्रेस भड़क गई है। उसने सोमवार को राज्यसभा में शुन्यकाल के दौरान इस मुद्दे जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस ने केंद्र पर सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा, उसके नेताओं को राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस के इन आरोपों का भाजपा सदस्यों ने कड़ा विरोध किया।

लोकसभा में पारित हुआ मोटर वाहन संशोधन विधेयक

नई दिल्ली : सरकार लोकसभा में मोटर वाहन संशोधन विधेयक पारित करने में सफल रही। सरकार को अब इसे राज्यसभा में पारित कराना होगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चर्चा का जवाब दिया। विधेयक के अनुसार दुर्घटना में मौत की स्थिति में न्यूनतम मुआवजे के रूप में पांच लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

रायपुर के होटल में लगी आग जिंदा जले पांच कारोबारी

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित होटल तुलसी में रविवार-सोमवार को दरमियानी रात आग लग गई। बेकाबू आग ने भूतल से पांचवें मंजिल तक को अपनी चपेट में ले लिया। होटल में 12 लोग ठहरे थे। ये सभी कारोबारी थे। इनमें से पांच आग में जिंदा जल गए। शेष सात कारोबारियों और होटल में काम करने वाले पांच लोगों ने कूदकर किसी तरह जान बचाई।

कारोबार ▶ पृष्ठ 10

मोबाइल के माध्यम से निकाल सकेंगे ईपीएफ

नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 'उमंग' के जरिये ईपीएफ दावों को निपटान की तैयारी में है। ऐसा होने पर संगठित क्षेत्र के कर्मचारी मोबाइल एप 'उमंग' से ईपीएफ निकाल सकेंगे। हालांकि इसके लिए अभी कोई समय-सीमा नहीं तय की गई है। सोमवार को श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि इससे करीब 4.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा।

स्पोर्ट्स ▶ पृष्ठ 13

भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता खिताब

नई दिल्ली : भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व लीग के दूसरे दौर के फाइनल में निली को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर खिताब जीत लिया। भारतीय टीम ने वेस्ट वेल्कम में खेले जा रहे टूर्नामेंट के फाइनल में एक थादगार जीत दर्ज की। भारत ने जून-जुलाई में होने वाले महिला हॉकी विश्व लीग के सेमीफाइनल में भाग लेना भी सुनिश्चित कर लिया है।

हल की तलाश

सोलह विपक्षी दलों ने आयोग से मिलकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की, बुधवार को राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी दल



जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की विश्वसनीयता पर उठे सियासी सवालों को तूल पकड़ता देख चुनाव आयोग ने अब इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है। आयोग ने 16 विपक्षी दलों की ईवीएम की खामियों को दूर करने या फिर भविष्य के चुनावों को बैलेट पेपर के जरिये ही कराने की मांग के महंजर यह बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने सोमवार को चुनाव आयोग से मुलाकात कर बैलेट पेपर की पुरानी प्रणाली पर लौटने की मांग की थी। विपक्षी दलों ने ईवीएम विवाद पर एकजुट होकर काम करने की रणनीति बनाई है। इसी के तहत चुनाव आयोग में शिकायत के बाद उन्होंने बुधवार को राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है।

राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद की अगुआई में 16 पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को यहां चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, हमारी शिकायतों पर आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करने की बात कही है। इस बैठक में ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठे



सवालों पर चर्चा की जाएगी। विपक्षी दलों ने आयोग को सौंपे जापन में कहा है कि हाल के चुनावों में ईवीएम को लेकर लोगों का भरोसा टूट गया है, क्योंकि बटन दबाने पर एक पार्टी विशेष के पक्ष में ही वोट गिरेने की घटनाएँ सामने आई हैं। इसीलिए चुनाव में लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए आयोग को ईवीएम की खामियाँ दूर करने और पेपर ट्रेल मशीन की व्यवस्था होने तक बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने चाहिए। विपक्षी दलों ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने का भी आयोग को सुझाव दिया है।

चुनाव आयोग से मुलाकात से पहले सुबह संसद भवन में गुलाम नबी की अगुआई में इन दलों के नेताओं की

धृतराष्ट्र वन गया है चुनाव आयोग : केजरीवाल

नई दिल्ली : अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आयोग की तुलना धृतराष्ट्र से की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब उस धृतराष्ट्र के किरदार में आ गया है जिसका मकसद सिर्फ अपने बेटे दुर्गाधन यानी भाजपा को सत्ता दिलाना हो गया है।

बैठक हुई। इसमें कांग्रेस के कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा के साथ ईवीएम विवाद को सबसे पहले तूल देने वाली बसपा के सतीश मिश्र, गुणमूल कांग्रेस के सुखेंद्र शेखर बरा, सपा के नीरज शेखर और जदयू के अनवर अली के अलावा माकपा, भाकपा, द्रमुक, राकपा व राजद आदि के भी नेताओं ने शिरकत की। इसी बैठक में ईवीएम पर एकजुट रणनीति के साथ पहले चुनाव आयोग और फिर राष्ट्रपति से मिलने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद नहीं थे। पार्टी सूत्रों ने हालांकि बताया कि राष्ट्रपति से विपक्षी दलों की मुलाकात के दौरान अखिल के प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने की संभावना है।

ईवीएम पर याचिकाओं की सुनवाई 13 को

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। याचिकाओं में वोटर रजिफाइड पेपर आइट्र ट्रेल से लेंस किए बगैर ईवीएम का प्रयोग किए जाने को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने समाजवादी पार्टी के नेता अताउर रहमान की याचिका पर अलग से सुनवाई करने से माना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसी तरह के मुद्दों पर अन्य याचिकाओं की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। इसी समय आप अपने मुद्दे भी रखेंगे।

ईवीएम पर याचिकाओं की सुनवाई 13 को

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। याचिकाओं में वोटर रजिफाइड पेपर आइट्र ट्रेल से लेंस किए बगैर ईवीएम का प्रयोग किए जाने को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने समाजवादी पार्टी के नेता अताउर रहमान की याचिका पर अलग से सुनवाई करने से माना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसी तरह के मुद्दों पर अन्य याचिकाओं की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। इसी समय आप अपने मुद्दे भी रखेंगे।

वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई टली

जासं, नई दिल्ली : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में पटयाला हाउस कोर्ट में सोमवार को आरोपपत्र पर सज़ाान लेने की कार्यवाही नहीं हो सकी। विशेष सीबीआई जज विरेंद्र कुमार गोयल ने सुनवाई को 24 अप्रैल तक के लिए टाल दिया। सीबीआई द्वारा दाखिल किए गए 450 से अधिक पेज के आरोपपत्र में मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी सहित कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया गया है। सभी दस्तावेजों की समीक्षा पूरी होने के बाद अदालत को आरोपपत्र पर सज़ाान लेते हुए सभी आरोपियों को खिलाफ पेशी समन जारी करने को लेकर निर्णय लेना था, जिसे अब 14 दिन के लिए टाल दिया गया है।

सीबीआई ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री के पास उनकी तय आय से 10 करोड़ अधिक संपत्ति पाई गई थी। यह राशि उनकी निर्धारित आय से 192 प्रतिशत अधिक है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए वीरभद्र सिंह ने यह आवंध्यकम अर्जित की थी। आईपीसी की धारा- 109 (उत्कृष्टता), 465 (जालसाजी) व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें कुल 222 लोगों को मुख्यमंत्री के खिलाफ गवाह बनाया गया है।

आतंकियों की प्रशंसा करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आतंकियों की प्रशंसा करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से बन रही है, वह एक बानगी भारत और आस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त घोषणापत्र में उभरे आतंकियों की प्रशंसा करने के बाद और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैलकम टर्नबुल और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगुआई में द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी किया है। इसमें दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप का निंदा की। साथ ही इसमें आतंकियों को समर्थन या प्रश्रव देने वालों या गलत चर्चों से उनका प्रचार को पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

भारत और आस्ट्रेलिया ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करने की प्रतिबद्धता है। सौर ऊर्जा और कोयला

भारत और आस्ट्रेलिया ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करने की प्रतिबद्धता है। सौर ऊर्जा और कोयला

नापाक निर्णय ▶ पाकिस्तान ने उभरे आतंकियों को बिगाड़ने वाला कदम

जाधव को सख्त सजा भारत ने कहा-मजिस्ट्रेट हत्या

भारत ने 11 पाक कैदियों की रिहाई रोकी, बासित को तलब कर जताया गुस्सा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आतंक को पनाह देने के मुद्दे पर दुनियाभर में बेनकाब हो रहे पाकिस्तान ने सोमवार को एक ऐसा कदम उठाया, जो भारत के साथ रिश्तों को पटरी पर लाने की उम्मीदों को और धक्का पहुंचाएगा। पिछले वर्ष ईरान में पकड़े गए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। इस पर विदेश सचिव एस. जयशंकर ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया और भारत की नाराजगी से अवगत कराया। जयशंकर ने बासित को डिमार्श (कूटनीतिक विरोध पत्र) सौंपकर कहा कि यदि जाधव को फांसी दी गई, तो भारत इसे सुनिश्चित हथ्था मानेगा। भारत ने 11 पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई भी रोक दी है।

सोमवार देर शाम को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने सीनेट को बताया कि कानून के मुताबिक जाधव को मौत की सजा सुनाई गई है। जाधव को भारतीय खुफिया एजेंसी 'र' के एजेंट के रूप में बलूचिस्तान और कराची में विद्रोह भड़काने का दोषी बताया गया है।

कानून का पालन नहीं किया गया : विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाक उच्चायुक्त बासित से कहा कि जाधव को न्याय प्रक्रिया का पालन किए बगैर सजा सुनाई गई है। भारत ने कहा कि जाधव का पिछले साल ईरान से अग्रहरण किया गया था। पाकिस्तान में उनकी मौजूदगी को साबित नहीं किया गया। भारतीय उच्चायुक्त ने जाधव से मुलाकात का 13 बार आग्रह किया। एक बार भी नहीं मिलने दिया गया। भारतीय उच्चायुक्त को एक बार भी नहीं बताया कि जाधव पर मुकदमा चल रहा है।

पाक सेनाध्यक्ष ने की पुष्टि : सैन्य अदालत द्वारा जाधव को सभी आरोपों का दोषी मानने के बाद पाक सेनाध्यक्ष कमर बाजवा ने सोमवार को फांसी की सजा की पुष्टि कर दी। पाक सेना की मीडिया विंग ने बताया कि जाधव पर पाक आर्मी एक्ट और सरकार गोपनीयता कानून के तहत मुकदमा चलाया गया था।

जाधव के मुंबई के घर में सनटा

पाक ने लगाए मनगढ़ंत आरोप

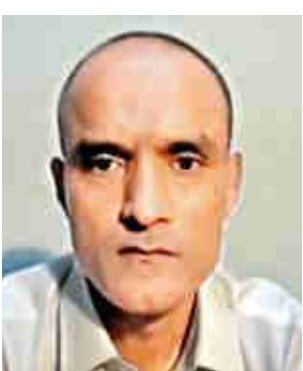
3 मार्च, 2016 को गिरफ्तारी के वक्त जाधव भारतीय नौसेना में कमांडर थे।

मजिस्ट्रेट के समक्ष उन्होंने रॉ का एजेंट होने की बात मान ली।

जाधव ने नाम बदलकर हुसैन मुबारक पटेल कर लिया था।

रॉ ने बलूचिस्तान और कराची में जासूसी के लिए भेजा था।

उन्हें ईरान के रास्ते बलूचिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया था।



कुलभूषण जाधव।

अंतरराष्ट्रीय मानदंड का उल्लंघन करती है पाक की सैन्य अदालतें

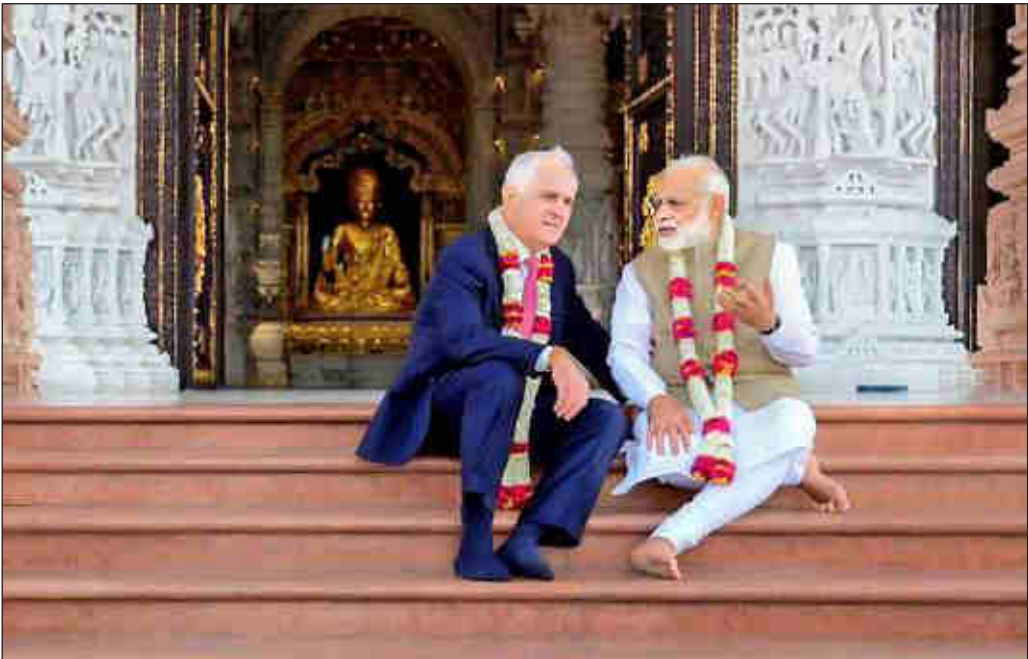
लंदन, प्रेटर : एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में सुनाई गई फांसी की सजा की आलोचना की है। एमनेस्टी ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत प्रणाली ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को कुचल देती है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल में दक्षिण एशिया के निदेशक बिराज पटनायक ने कहा, 'कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा से एक बार फिर सामने आ गया है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत प्रणाली किस तरह अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को कुचलती है।'

गुप्तचुप तरीके से अधिनिक सुना दी गई सजा

जाधव को जिस गोपनीय तरीके से फांसी की सजा सुनाई गई है, वह अपने आप में काफी अनूठी है। स्वयं सरताज अजीज कुछ महीने पहले कह चुके हैं कि जाधव के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उसके खिलाफ सिर्फ कुछ बयान हैं। यह बयान अजीज ने सीनेट के सामने सात दिसंबर, 2016 को दिया था।

पटनायक ने एक बयान में कहा है, 'बचाव करने का अधिकार छीन लिया जाता है और सैन्य अदालत गोपनीय तरीके से संचालित होती है। इस तरह ऐसी अदालत न्याय नहीं, बल्कि उसका मजाक करती है।' पटनायक ने कहा कि एमनेस्टी हमेशा से हर परिस्थिति में मौत की सजा का विरोध करता आया है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और तोड़फोड़ का दोषी ठहराने के बाद फांसी की सजा सुनाई है। 46 वर्षीय पूर्व नौसेना अधिकारी को कोर्ट मार्शल में सुनाई गई सजा की पुष्टि पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने की है।



नई दिल्ली में सोमवार को अक्षरधाम मंदिर में अपने आस्ट्रेलियाई समकक्ष मैलकम टर्नबुल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

रणनीतिक साझेदारी की नई शुरुआत

प्रधानमंत्री मोदी की पिछली आस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान ही भारत ने स्पष्ट किया था कि आस्ट्रेलिया उसकी रणनीतिक योजना में अहम स्थान रखता है। सोमवार को हुई बातचीत ने रणनीतिक साझेदारी को अब ज्यादा प्रायोगिक स्तर पर ले जाने का दस्ता बनाया है। अगले वर्ष दोनों देशों की सेनाओं के बीच पहली बार संयुक्त युद्धाभ्यास किया जाएगा। पिछले वर्ष सिर्फ युद्धाभ्यास की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही दोनों देशों के रक्षा सचिव और विदेश सचिव को एक साथ बातचीत होगी। यह रणनीतिक वार्ता को आगे बढ़ाने का एक नया तरीका है जिसमें तेजी से फैसले हो सकेंगे।

अनंतनाग उपचुनाव 25 मई तक टला

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में अनंतनाग लोकसभा सीट का उपचुनाव 25 मई तक स्थगित कर दिया है। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा कानून और व्यवस्था को अनुकूल नहीं बताए जाने के बाद आयोग ने यह निर्णय लिया है। इस सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होना था।

चुनाव आयोग की अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य प्रशासन समझता है कि शराबी तत्व चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए हिंसक तरीके अपना सकते हैं। उसकी ओर से रविवार को श्रीनगर उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा का भी जिक्र किया गया है। अनंतनाग में चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के लिए एक जून की तारीख तय की गई है। पुनर्मतदान की आशंका को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के लिए इतना लंबा समय दिया गया है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पिछले वर्ष जून में लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से अनंतनाग लोकसभा सीट रिक्त है। उधर चुनाव आयोग की घोषणा से पहले श्रीनगर संसदीय सीट के लिए हुए उपचुनाव में व्यापक हिंसा के बाद अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में सत्तापक्ष और विपक्ष बंटा हुआ नजर आया। दोनों पक्षों ने उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा और कम मतदान के लिए एक-दूसरे पर आरोप लगाए। ध्यान रहे कि रविवार को मतदान के दिन बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से सोमवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कहा कि चुनाव स्थगित होने से हिंसा और भड़केंगी। वहीं सत्तापक्ष ने कहा कि हमें वोट के लिए जान नहीं चाहिए, हालात सामान्य होने पर ही चुनाव होना चाहिए।



राजम की बैठक में भाग लेते भाजपा के सहयोगी दलों के नेता।

में भी सरकार ने अर्थव्यवस्था का संचालन किया और तीन साल के कार्यकाल के बाद भी भ्रष्टाचार के दाग से पूरी तरह दूर है, उसने हर किसी के मन में राजग सरकार के लिए स्थान बनाया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मोदी के नेतृत्व और कठोर फैसले लेने की उनकी क्षमता के कारण राजग लगातार बढ़ रहा है। तेदया नेता चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पूर्ण बहुमत मिला और उत्तर प्रदेश की जीत ने उनकी लोकप्रियता पर फिर से मुहर लगाई है। मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है और विकास के लिए ऐसी ही कुशल सरकार की जरूरत होती है। जाहिर तौर पर उनका संकेत 2019 चुनाव की ओर था।

राष्ट्रपति चुनाव नहीं था एजेंडों में : जेएनडी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव इस बैठक का एजेंडा नहीं था। जब वक्त आएगा तो उस मुद्दे पर चर्चा होगी। बहरहाल इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि विपक्षी खेमे को ईंट का जवाब पथर से देने के साथ-साथ यह बैठक राष्ट्रपति चुनाव से पहले एकजुटता की झलक भी है।

हिमाचल के सीएम वीरभद्र को ईडी ने किया तलब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को अब मनी लाँडिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने हाजिर होना पड़ेगा। ईडी ने उन्हें सीएस भेज कर गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होकर पृष्ठताछ में सहयोग करने को कहा है। ईडी वीरभद्र को कई संपत्तियों को पहले ही तलब कर चुका है।

ईडी मनी लाँडिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत वीरभद्र सिंह के बैंक खाते में अचानक जमा होने के तहत वीरभद्र सिंह को तलब कर चुका है। वह इस मामले में उनकी बयान दर्ज कराना चाहता है। इसलिए उन्हें एक बार पेशी के सामने जारी कर गुरुवार को अधिकारी के सामने होकर पेश होने को कहा गया है। इससे पहले ऐसे समूहों के जवाब में उन्होंने अपनी आधिकारिक संपत्ति का हवाला देकर उपलब्ध के अनुसार समर्थता जता दी थी। ईडी उनकी पत्नी प्रतिभा और बेटे विक्रमादित्य के बयान पहले ही ले चुका है।

वीरभद्र सिंह के खिलाफ केंद्र में इम्पार्त मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति हासिल करने का मामला सीबीआई ने दर्ज किया था। सीबीआई आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। उसने आरोपपत्र में कहा है कि इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने दस करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई जो उनकी घोषित आय के मुकाबले 192 प्रतिशत अधिक थी। इस मामले में वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और बेटे के अलावा अन्य कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने इस मामले में सितंबर, 2015 में शिकायत दर्ज की थी। सीबीआई ने दर्ज शिकायत के आधार पर ही ईडी ने भी मनी लाँडिंग कानून के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अब तक उनके और परिवार के लोगों की 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। वीरभद्र सिंह ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियां उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही हैं।



वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई टली

जासं, नई दिल्ली : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में पटयाला हाउस कोर्ट में सोमवार को आरोपपत्र पर सज़ाान लेने की कार्यवाही नहीं हो सकी। विशेष सीबीआई जज विरेंद्र कुमार गोयल ने सुनवाई को 24 अप्रैल तक के लिए टाल दिया। सीबीआई द्वारा दाखिल किए गए 450 से अधिक पेज के आरोपपत्र में मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी सहित कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया गया है। सभी दस्तावेजों की समीक्षा पूरी होने के बाद अदालत को आरोपपत्र पर सज़ाान लेते हुए सभी आरोपियों को खिलाफ पेशी समन जारी करने को लेकर निर्णय लेना था, जिसे अब 14 दिन के लिए टाल दिया गया है।

सीबीआई ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री के पास उनकी तय आय से 10 करोड़ अधिक संपत्ति पाई गई थी। यह राशि उनकी निर्धारित आय से 192 प्रतिशत अधिक है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए वीरभद्र सिंह ने यह आवंध्यकम अर्जित की थी। आईपीसी की धारा- 109 (उत्कृष्टता), 465 (जालसाजी) व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें कुल 222 लोगों को मुख्यमंत्री के खिलाफ गवाह बनाया गया है।

न्यूज गेलरी

सीरिया में रासायनिक हमले के खिलाफ शांति सभा

नई दिल्ली : सीरिया में रासायनिक हमले में जान गंवाने वाले 27 से अधिक मासूमों की आत्मा की शांति के लिए राजघाट पर शांति सभा का आयोजन किया गया। इसकी अगुआई नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने की। इस मौके पर उन्होंने विश्व में जारी हिंसा और उसमें मासूमों के शिकार होने पर चिंता जताते हुए वैश्विक नेताओं से दुनिया को युद्ध और संघर्ष से बचाने की भी अपील की। सभा में धर्मगुरु, अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ काफी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। इस मौके पर सत्यार्थी ने कहा कि बच्चे कभी भी हिंसा, संघर्ष या युद्ध का कारण नहीं होते। उल्टे वे ऐसी स्थितियों में सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं।

दिल्ली के पेट्रोल पंप प्रत्येक रविवार नहीं होंगे बंद

नई दिल्ली : कंसोर्टियम ऑफ इंडियन पेट्रोल डीलर्स (सीआइपीडी) के घोषित आंदोलन में दिल्ली-एनसीआर के पेट्रोल पंप संचालक शामिल नहीं होंगे। बता दें कि सीआइपीडी ने तेल कंपनियों पर कमीशन बढ़ाने के मुद्दे पर दबाव बढ़ाने के लिए 10 मई से हर रविवार पेट्रोल पंप बंद रखने की घोषणा की है। रविवार को कुरुक्षेत्र में सीआइपीडी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। वहीं, इस फैसले से अलग जानकारी देते हुए ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने कहा कि इस विरोध में दिल्ली समेत 21 राज्यों के पेट्रोल डीलर्स शामिल नहीं होंगे।

जब्त बसों का अब परमिट रद्द करेगा परिवहन विभाग

नई दिल्ली : निजी बस आपरेटर्स द्वारा अवैध तरीके से राजधानी में चलाई जा रही बसों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले पांच दिनों में ऐसी करीब 300 से अधिक बसें जब्त की हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि ये बसें परमिट शर्तों का उल्लंघन कर अवैध रूप से दिल्ली में चल रही थीं। अन्य राज्यों से आने वाली बसों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। इसमें एए आभारित सेवा के तहत चलने वाली बसें भी शामिल हैं। विभाग अब इन बसों का परमिट रद्द करेगा। जिन राज्यों की बसों को जब्त किया गया है, उन राज्यों की सरकारों को भी इन बसों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए परिवहन विभाग ने पत्र लिखा है।

हरियाणा भवन के बाहर कैब चालकों ने किया प्रदर्शन

नई दिल्ली : हरियाणा भवन के बाहर टैक्सी और कैब चालकों ने प्रदर्शन कर हरियाणा सरकार से बड़ा हुआ रोड पैसेंजर टैक्स वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन और दिल्ली टैक्सी ट्रिस्ट ट्रॉसपोर्ट एंड ट्रू ऑपरेटर्स एसोसिएशन (डीटीटीटीओए) समेत अन्य संगठनों के चालक शामिल थे। बाद में प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा भवन के अधिकारियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले चालकों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फाड़ा। प्रदर्शन से कोपरिनकस मार्ग और मंडी हाउस पर जाम की स्थिति बनी रही।

तंजानिया उच्चायोग पहुंचा लूट का शिकार पीड़ित परिवार

नई दिल्ली : मध्य जिला के करोल बाग इलाके में लूट का शिकार हुई तंजानिया की बुजुर्ग महिला परिवार के साथ तंजानिया उच्चायोग में अधिकारियों से मिली। घटना के दो दिन बाद भी कोई कार्रवाई न होने से परेशान पीड़ित परिवार ने अधिकारियों को आपबीती सुनाई और मदद की गुहार लगाई। तंजानिया उच्चायोग ने मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी। डेढ़ साल के बेटे का इलाज करने के लिए तंजानिया से भारत आए आरिफ ने बताया कि पुलिस ने जांच के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने सोमवार को भी जांच अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। कोई सहयोग न मिलने पर वे तंजानिया उच्चायोग पहुंचे। आरिफ ने बताया कि उन्होंने उच्चायोग अधिकारियों से मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय के जरिये कार्रवाई करने की मांग की।

निगम का रण

पंजाब चुनाव में उम्मीद के अनुरूप सफलता न मिलने और गोवा में शिकस्त से परेशान केजरीवाल नाराज लोगों के घर अकेले ही पहुंच जा रहे हैं।



उफ़! ये गर्मी...

तेज धूप और हवा से बचने की कोशिश करती युवतियां। बता दें कि दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

जागरण

राजधानी के फाइव स्टार होटलों को एनजीटी ने थमाया नोटिस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 की ध्वजियां उड़ाकर कचरा फैला रहे दिल्ली के कई फाइव स्टार होटलों, मॉल, अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों और रेजीडेंशियल सोसाइटीज को नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने इनसे यह भी पूछा है कि क्यों न उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाए।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एनजीटी की पीठ ने इन्हें दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। एनजीटी का कहना है कि सीवेज को ट्रीट करने में नाकाम रहने वाली इन संस्थाओं पर क्यों न

सख्ती

► **एनजीटी ने किया कचरा डालने वाले फाइव स्टार होटलों, अस्पतालों से सवाल**

► **पूछा क्यों न लगाया जाए जुर्माना**

पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाए।

एनजीटी ने जिनको नोटिस जारी किए हैं उनमें आठ होटल व दो अस्पताल नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में हैं जबकि सात होटल, चार मॉल, पांच अस्पताल, रेलवे और बस स्टेशन की पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में हैं। इसके अलावा ऐसे कई संस्थान उत्तरी और दक्षिण नगर निगम क्षेत्र में भी हैं।

एनजीटी ने यह आदेश इसकी एक समिति

की रिपोर्ट के आधार पर किया है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि इस तरह वे संस्थान कचरे को सही ढंग से निपटाने में नाकाम रहे हैं। इस समिति में पर्यावरण व शहरी विकास मंत्रालयों के अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगमों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। साथ ही इसमें चार स्वतंत्र विशेषज्ञ भी बतौर सदस्य शामिल थे। इनमें एनजीटी के पूर्व सदस्य जीके पांडेय और डी के अग्रवाल, डा. आर डलवानी और डा. राशिद हसन शामिल हैं। एनजीटी ने समिति को सभी फाइव स्टार होटलों, 200 बेड से अधिक की क्षमता वाले अस्पतालों और सहकारी आवासीय सोसाइटी के निरीक्षण का आदेश दिया था।

कई कॉलेजों को मिलेगा नए कोर्स का तोहफा

अभिनव उपाध्याय, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में नए सत्र से कई कॉलेजों को नए कोर्स का तोहफा मिल सकता है। डीयू में 28 फरवरी को हुई कार्यकारी परिषद की बैठक में नए कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इस पर अंतिम फैसला कुलपति को लेना है।

डीयू के 15 से अधिक कॉलेजों में नए कोर्स शुरू किए जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि डीयू की अकादमिक मामलों की स्थायी समिति ने नए कोर्स को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा विद्वत परिषद की भी हरी झंडी मिल गई है। डीयू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसकी बहुत संभावना है कि आने वाले सत्र से कॉलेजों में नए कोर्स शुरू हो जाएंगे। कॉलेज इन कोर्स के लिए अपने यहां अतिरिक्त सीटें बढ़ाएंगे। यही नहीं, आवश्यकता हुई तो फैकल्टी भी बढ़ाएंगे। एक कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कोर्स शुरू करने की अनुमति देने में बहुत देर कर रहा है। अनुमति मिलने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इन्हें संचालित करने के लिए धन की मांग की जाएगी। कुलपति से नए कोर्स संचालित करने की मंजूरी मिलने के बाद आत्मगम सनातन धर्म कॉलेज अपने यहां बॉटनी, जुलॉजी, हिंदी पत्रकारिता और संस्कृत में ऑनर्स कोर्स शुरू कर सकता है। इस संबंध में उसने डीयू प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया है। इसके अलावा नार्थ कैंपस के प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज ने भी पांच नए कोर्स संचालित करने की अनुमति मांगी है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी मंजूरी नहीं दी है। हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ.

तेयारी

► **कोर्स शुरू करने के साथ ही सीटें भी बढ़ाएंगे कॉलेज**

► **15 से अधिक कॉलेजों में शुरू हो सकते हैं कोर्स**

रमा ने कहा, हम हिंदी पत्रकारिता, साइकोलॉजी, पोलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी व फिर्लांसफी का कोर्स शुरू करना चाहते हैं। इस संबंध में कुलपति को प्रस्ताव भी भेजा है, लेकिन अभी से नए कोर्स को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा विद्वत परिषद की भी हरी झंडी मिल गई है। डीयू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसकी बहुत संभावना है कि आने वाले सत्र से कॉलेजों में नए कोर्स शुरू हो जाएंगे। कॉलेज इन कोर्स के लिए अपने यहां अतिरिक्त सीटें बढ़ाएंगे। यही नहीं, आवश्यकता हुई तो फैकल्टी भी बढ़ाएंगे। एक कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कोर्स शुरू करने की अनुमति देने में बहुत देर कर रहा है। अनुमति मिलने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इन्हें संचालित करने के लिए धन की मांग की जाएगी। कुलपति से नए कोर्स संचालित करने की मंजूरी मिलने के बाद आत्मगम सनातन धर्म कॉलेज अपने यहां बॉटनी, जुलॉजी, हिंदी पत्रकारिता और संस्कृत में ऑनर्स कोर्स शुरू कर सकता है। इस संबंध में उसने डीयू प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया है। इसके अलावा नार्थ कैंपस के प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज ने भी पांच नए कोर्स संचालित करने की अनुमति मांगी है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी मंजूरी नहीं दी है। हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ.



26 हजार घंटियों से बने हनुमान

भगवान हनुमान के विभिन्न स्वरूपों के बारे में तो सभी जानते होंगे, लेकिन दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इनका नया स्वरूप देखा जा सकता है। यहां 26 हजार घंटियों से 25 फीट ऊंचे हनुमान को दर्शाया गया है। 11 से 30 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रदर्शनी की खासियत राजस्थानी परंपरा का वह आदमकद (8 फीट लंबा) कांवड़ बॉक्स भी है जो पांच मिनट के भीतर चित्रों के जरिये हनुमान के जन्म से लेकर लंका दहन, श्रीराम के राजतिलक और पाताल में अंगूठी फेंकने तक की उनकी सारी जीवन यात्रा बयां कर देता है।

बदसलूकी ► यूसीएमएस में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया

एमबीबीएस के छात्रों से की रैगिंग, जबरन पिलाई शराब

एंटी रैगिंग हेल्पलाइन को मिली शिकायत, कॉलेज प्रशासन ने शुरू की जांच

स्वदेश कुमार, नई दिल्ली

जीटीबी अस्पताल में आंखों के इलाज में लापरवाही का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब इसके परिसर स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज (यूसीएमएस) के एमबीबीएस छात्रों के साथ रैगिंग मामले से हड़कंप मच गया है। दो छात्रों ने सेंट्रलाइज्ड एंटी रैगिंग हेल्पलाइन को ई-मेल भेज शिकायत की है। इसमें एक छात्र दलित है।

आरोप है कि द्वितीय वर्ष के छात्रों ने पहले वर्ष के छात्रों के साथ बदसलूकी की और गाली-गलौच कर जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के साथ एक छात्र को जबरन शराब भी पिलाई। सोमवार को शिकायत मिलते ही कॉलेज प्रशासन की एंटी रैगिंग कमेटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

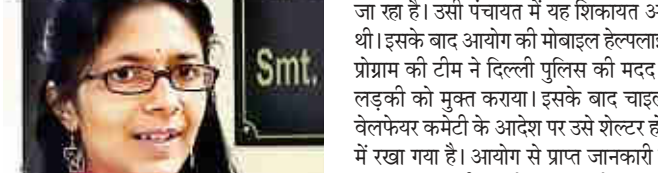
साथ ही पुलिस को भी सूचित किया गया है। हालांकि मामला दर्ज करने के लिए पुलिस

छात्रों ने की अलग मेस की मांग

यूसीएमएस के कुछ छात्रों ने बताया कि रैगिंग से बचाने के लिए प्रथम वर्ष के छात्रों को अलग हॉस्टल में रखा जाता है, लेकिन मेस एक ही है। मेस में खाना खाने के लिए सीनियर और जूनियर छात्र सभी जाते हैं। ऐसी जगह पर रैगिंग का अंदेश बना रहता है। उनका कहना है कि अलग हॉस्टल के साथ ही प्रथम वर्ष के छात्रों का मेस भी अलग कर दिया जाए।

कॉलेज की तरफ से शिकायत का इंतजार कर रही है। शिकायत में बताया गया कि शुक्रवार को एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की प्रोफेशनल परीक्षा (सप्लीमेंट्री) का रिजल्ट आया था। इसमें पास होने वाले कुछ छात्र शाम करीब आठ बजे हॉस्टल के गेट के पास पार्किंग में शराब पीते हुए जश्न मना रहे थे। इसी दौरान कुछ प्रथम वर्ष के छात्र पहुंच गए। आरोपियों ने उन छात्रों को रोक जबरन शराब पिलाने की कोशिश की। एक छात्र को उन्होंने

रही है। शिकायत में बताया गया कि शुक्रवार को एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की प्रोफेशनल परीक्षा (सप्लीमेंट्री) का रिजल्ट आया था। इसमें पास होने वाले कुछ छात्र शाम करीब आठ बजे हॉस्टल के गेट के पास पार्किंग में शराब पीते हुए जश्न मना रहे थे। इसी दौरान कुछ प्रथम वर्ष के छात्र पहुंच गए। आरोपियों ने उन छात्रों को रोक जबरन शराब पिलाने की कोशिश की। एक छात्र को उन्होंने



► **डीसीडब्ल्यू ने मुखर्जी नगर स्थित एक घर से लड़की को कराया मुक्त**

► **घरेलू सहायिका का कर रही थी काम, आठ माह से नहीं मिला वेतन**

बंधुआ मजदूर कानून के तहत लड़की को मदद करने को कहा है।

स्वाति मालीवाल ने बताया कि आयोग की ओर से महिला पंचायत नामक अभियान चलाया

जा रहा है। उसी पंचायत में यह शिकायत आई थी। इसके बाद आयोग की मोबाइल हेल्पलाइन

प्रोग्राम की टीम ने दिल्ली पुलिस की मदद से लड़की को मुक्त करवाया। इसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश पर उसे शेल्टर होम में रखा गया है। आयोग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, लड़की पिछले आठ माह से काम कर रही थी। अब तक उसे वेतन नहीं मिला है। उसे खाना भी नहीं दिया जाता था और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। आयोग का कहना है कि लड़की ने बताया कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है और पिता बीमार रहते हैं। उसके चाचा बड़ाने के लिए उसे गांव से पटना लाए थे, लेकिन बाद में उसे दिल्ली के शकूरपुर स्थित एक प्लेसमेंट एजेंसी को बेच दिया।

जा रहा है। उसी पंचायत में यह शिकायत आई थी। इसके बाद आयोग की मोबाइल हेल्पलाइन

प्रोग्राम की टीम ने दिल्ली पुलिस की मदद से लड़की को मुक्त करवाया। इसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश पर उसे शेल्टर होम में रखा गया है। आयोग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, लड़की पिछले आठ माह से काम कर रही थी। अब तक उसे वेतन नहीं मिला है। उसे खाना भी नहीं दिया जाता था और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। आयोग का कहना है कि लड़की ने बताया कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है और पिता बीमार रहते हैं। उसके चाचा बड़ाने के लिए उसे गांव से पटना लाए थे, लेकिन बाद में उसे दिल्ली के शकूरपुर स्थित एक प्लेसमेंट एजेंसी को बेच दिया।

मुख्यमंत्री के आवास के ऊपर उड़ा झोन

विनित त्रिपाठी, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के ऊपर झोन उड़ने की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर उच्च अधिकारी और सिविल लाइंस थाना पुलिस हस्तक में आ गई। मुख्यमंत्री को सुरक्षा से जुड़ा मामला होने के कारण सिविल लाइंस थाना पुलिस की एक टीम जब मुख्यमंत्री आवास पहुंची तो पाता चला कि वहां का स्टाफ झोन कैमरे को उड़ाकर उसकी जांच कर रहा था। उसने बताया कि इसका

इस्तेमाल पार्टी के कार्यक्रमों के दौरान किया जाता है। पुलिस के अनुसार, सोमवार शाम करीब साढ़े छह बजे सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में 6 फ्लैग स्टाफ डेड स्थित मुख्यमंत्री आवास के ऊपर झोन कैमरा उड़ता हुआ दिखाई दिया। झोन कैमरा कुछ देर तक आवास के ऊपर उड़ता रहा, जिसे देख वहां मौजूद पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मी हस्तक में आ गया। उसने इसकी पीसीआर कॉल कर दी, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर उच्च अधिकारी हस्तक में आ गए।

कांग्रेस के बागी भी ठोक रहे ताल

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली

दिल्ली नगर निगम की सत्ता हासिल करने की जुगत में लगी कांग्रेस की रह उसके अपने मुश्किल कर रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पार्टी के कई नेता निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इससे पार्टी के घोषित प्रत्याशियों को विरोधी पार्टियों के साथ ही इनसे मुकाबला करना पड़ रहा है।

टिकट वितरण में पक्षपात का आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पार्टी हाईकमान विरोध शुरू कर दिया था। इसके साथ ही पार्टी के कई पदाधिकारियों व पापंदों ने बगावत कर निर्दलीय नामांकन पत्र भर दिया था। इसमें से कई लोगों को तो पार्टी ने भना लिया, लेकिन अब भी 30 से ज्यादा नेता मैदान में डटे हुए हैं।

परेशानी

► **30 से ज्यादा वार्डों में मिल रही है अपनों से चुनौती**

► **कई मंडल अध्यक्ष और पापंद भी बगावत की राह पर**

इसमें कांग्रेस के कई ब्लॉक अध्यक्ष और महिला कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल हैं। नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि भी खत्म हो गई है। ऐसे में अब इनका चुनाव लड़ना तब है। फिर भी पार्टी इन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि वे अपना चुनाव प्रचार करने के बजाय पार्टी के उम्मीदवार के साथ खड़े हो जाएं।

पार्टी को तीनों नगर निगमों में बागियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बगावत पूर्वी दिल्ली नगर निगम में है। यहां के 14 वार्डों में कांग्रेस के बागी चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें जनता कॉलोनी के पापंद जाकिर खान भी शामिल हैं। वहीं, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के दिल्ली गेट से कांग्रेस के पापंद रमेश दत्ता सहित 13 कांग्रेसी अपनी ही पार्टी के सामने चुनौती

बदसलूकी ► यूसीएमएस में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया

एमबीबीएस के छात्रों से की रैगिंग, जबरन पिलाई शराब

मामले की जांच की जा रही है। शिकायतकर्ताओं का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। कमेटी के सामने जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

– डॉ. वीपी गुप्ता, प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज

शराब पिला भी दी जबकि कुछ छात्र वहां से निकल गए। आरोपियों ने उनमें से एक दलित छात्र को जातिसूचक शब्दों से संबोधित किया और गाली-गलौच भी की। जैसे-तैसे छात्र उनके चंगुल से भाग निकले। शिकायतकर्ता ने अपना नाम न बताते हुए दो आरोपियों के नाम उत्पल कांत और सोमर गठी बताया है।

सूत्रों के अनुसार, शिकायत शनिवार को रैगिंग से बचाने के लिए प्रथम वर्ष के छात्रों को अलग हॉस्टल में रखा जाता है, लेकिन दो दिन अवकाश होने के कारण कोई कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। सूत्रों ने बताया कि करीब दस दिन पहले भी प्रथम वर्ष के एक छात्र के साथ कॉलेज के मेस में मारपीट हुई थी। पीड़ित ने कॉलेज प्रशासन को इसकी शिकायत दी, लेकिन बाद में मामला सुलझा लिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मानव तस्करी का अड्डा बन गई है दिल्ली : स्वाति मालीवाल

जा रहा है। उसी पंचायत में यह शिकायत आई थी। इसके बाद आयोग की मोबाइल हेल्पलाइन प्रोग्राम की टीम ने दिल्ली पुलिस की मदद से लड़की को मुक्त करवाया। इसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश पर उसे शेल्टर होम में रखा गया है। आयोग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, लड़की पिछले आठ माह से काम कर रही थी। अब तक उसे वेतन नहीं मिला है। उसे खाना भी नहीं दिया जाता था और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी।

आयोग का कहना है कि लड़की ने बताया कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है और पिता बीमार रहते हैं। उसके चाचा बड़ाने के लिए उसे गांव से पटना लाए थे, लेकिन बाद में उसे दिल्ली के शकूरपुर स्थित एक प्लेसमेंट एजेंसी को बेच दिया।

पीएमओ के सामने किसानों ने किया नग्न प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जंतर-मंतर पर पिछले 28 दिनों से धरना दे रहे तमिलनाडु के किसानों का धैर्य सोमवार को जवाब दे गया। प्रधानमंत्री संदेश मोदी से मुलाकात नहीं हो पाने से निराश किसानों ने साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बाहर सड़क पर ही नग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया।

किसान कर्ज माफी के साथ कावेरी नदी जल विवाद का स्थायी समाधान निकालने और फसलों की उचित मूल्य देने की मांग कर रहे थे। सोमवार को जंतर-मंतर से किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल पीएमओ में प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपने की उम्मीद में आया था। उनके साथ दिल्ली पुलिस के उच्चाधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। पीएमओ से बाहर निकलने के बाद प्रतिनिधिमंडल का एक सदस्य नग्न होकर सड़क पर दौड़ते हुए नारे लगाने लगा। इसके बाद तीन अन्य भी नग्न होकर नारे लगाने

लगे। यह देख वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ अन्य लोग भी हक्के-बक्के रह गए। आनन-फानन में चारों को कपड़े पहनाये गये। हालांकि, बाद में किसानों का प्रतिनिधिमंडल पुलिस से अधिकारियों के साथ फिर प्रधानमंत्री कार्यालय गया। इससे पहले तमिलनाडु के किसानों के इस प्रदर्शन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बॉलीवुड अभिनेता प्रकाश राज भी शामिल हो चुके हैं। कुछ दिन पहले आंदोलनरत दो किसानों ने पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश की थी।

पाददर्शी तरीके हुआ है चयन : कांग्रेस

वहीं नगर निगम चुनावों में प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस का दावा है कि इस बार पाददर्शी तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया गया है। इसके लिए पार्टी की ओर से स्थापित काल सेंटर से कार्यकर्ताओं को फोन करके आवेदकों के बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसके साथ ही राष्ट्रीय व प्रदेश के पर्ववक्षकों ने जिला अध्यक्षों के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार की थी। इसी के आधार पर योग्य प्रत्याशियों का चुनाव किया गया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन का कहना है कि अन्य पार्टियों की तुलना में कांग्रेस में कम असंतोष है। अन्य पार्टियों में तो फूट की स्थिति है।

पेश कर रहे हैं। इसी तरह से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से 6 वार्डों में पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है।

न्यूज गेलरी

सरोगेसी विधेयक पर स्थायी समिति ने मांगे लोगों के सुझाव

नई दिल्ली : व्यवसायिक उद्देश्य के लिए सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक का परीक्षण कर रही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति ने लोगों के सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस समिति का कार्यकाल भी गृज्यसभा सभापति ने 11 जुलाई तक बढ़ा दिया है। सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2016 को पिछले साल नवंबर में लोकसभा में पेश किया गया था। जनवरी में गृज्यसभा सभापति ने परीक्षण और विधेयक पर रिपोर्ट देने के लिए इसे स्थायी समिति को संदर्भित कर दिया था। समिति को इस पर अपनी रिपोर्ट 11 अप्रैल को दाखिल करनी थी। सरोगेसी ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई महिला किसी अन्य युगल के लिए बच्चे को जन्म देती है और जन्म के बाद बच्चे को उस युगल को सौंपने की सहमति देती है।

सिख दंगों पर विदेश मंत्रालय का बयान वापस लेने की मांग

नई दिल्ली : सत्तारूढ़ राजग में शामिल अकाली दल ने कनाडा के एक गृज्य द्वारा 1984 के सिख विरोधी दंगे पर पारित प्रस्ताव के खिलाफ भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान वापस लेने की मांग की है। सोमवार का शिरोमणि अकाली दल के सदस्य नरेश गुजराल ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि वह सरकार द्वारा स्वीकृत नरसंहार था। उसमें तीन दिन और तीन रातों तक निर्दोष सिखों का कत्ल किया गया। सरकार और पुलिस ने अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए इसमें दखल देने से इंकार कर दिया था।

शिक्षा का अधिकार कानून में संशोधन के लिए विधेयक पेश

नई दिल्ली : सरकार ने लोकसभा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पेश कर दिया। यह विधेयक प्राथमिक शिक्षकों को अनिवार्य न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए 2019 तक का समय देने के लिए पेश किया गया है। एक अप्रैल 2010 से लागू मौजूदा कानून के तहत इस शिक्षकों के लिए 31 मार्च 2015 से पांच वर्षों के भीतर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करना अनिवार्य है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को ‘बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) का अधिकार विधेयक 2017’ पेश किया। गृज्य सरकारों सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया जारी रखने में समर्थ नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है। विधेयक के विषय की व्याख्या और कारण में इसे स्पष्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि गृज्य सरकारों ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए समय बढ़ाने का आह्व किया है। समय बढ़ाने से प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। मंत्रालय ने अधिनियम में एक नया प्रावधान जोड़ा है। प्रावधान में छह से 14 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था है।

लोकसभा में अपने सांसद से शर्मिंदा हुई सरकार

नई दिल्ली : भाजपा के एक सांसद ने अपनी ही सरकार को शर्मिंदा कर दिया। सांसद ने सोमवार को एक केंद्रीय मंत्री के जवाब पर सवाल उठाया और उनसे दावे के समर्थन में सुबूतों देने की मांग की। उत्तर प्रदेश में घोसी से भाजपा सांसद हरिनाथगण राजभर ने केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय से प्रश्नकाल में बेकार हुए कामगारों की आर्थिक सुख्खा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने उन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद हुई मिलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2016-17 के दौरान 13 इकाइयां बंद हुईं और 2068 कामगार प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ‘उत्तर प्रदेश की कपड़ा मिल के संबंध में मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है। छंटनी से जो कामगार प्रभावित हुए हैं उन्हें आइडी एक्ट के तहत लाभ मिलेगा। वे अंतिम माह के वेतन का 50 फीसदी पा सकते हैं।’ ईएसआइसी द्वारा रजौव गांधी स्मार्क कल्याण योजना चलाई जाती है। इसके तहत छंटनी के शिकार कामगारों को उनके अंतिम माह के वेतन का 50 फीसदी मुहैया कराया जाता है।’ इस जवाब से असंतुष्ट राजभर ने कहा मंत्री जो कुछ कह रहे हैं वह वास्तविकता से परे हैं। उनसे आग्रह है कि वह इसका सुबूत मुहैया कराएं। पक्षा सक्ष के सदस्य पीछे हट गए, लेकिन कांग्रेसी सांसदों ने मेजें थपथपा कर स्वागत किया।

मई में ‘तेजस’, अक्टूबर में ‘उदय’ से सुधरेगी छवि

संजय सिंह, नई दिल्ली

पहली सेमी हाईस्पीड ‘तेजस’ ट्रेन मई में चलने की संभावना है। जबकि पहली डबल डेकर ‘उदय’ ट्रेन के लिए सितंबर अंत या अक्टूबर का पहला सप्ताह तय किया गया है। दोनों ट्रेनों में यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का इंतजाम होगा। इसी के साथ अगले तीन वर्षों में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली मेमू हाईस्पीड ट्रेनें चलने लगेंगी। ये प्रायः राजधानी वाले लंबे रूटों पर चलेंगी। जैसे दिल्ली-लखनऊ, दिल्ली-चंडीगढ़, दिल्ली-जयपुर और दिल्ली-भोपाल आदि।

पिछले एक साल के दौरान रेलवे ने 87 नई ट्रेनें चलाई, 51 ट्रेनों का मार्ग विस्तार किया तथा पांच ट्रेनों के फेरे बढ़ाए। इसके अलावा 350 ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ाई गई। इस दौरान संपन्न वर्ग के लिए महामना, मध्यम वर्ग के लिए हमसफर तथा आम आदमी के लिए अंत्योदय जैसी नए डिजाइन और सुविधाओं वाली ट्रेनों की शुरुआत भी की गई। इन ट्रेनों में पहली मर्बा एकदम नए फीचर दिए गए जिनमें सीसीटीवी कैमरे, फायर एक्सटिंग्विशर, एलईडी लाइट, डस्टविन, टॉयलेट आक्सीपैसी इंडीकेटर, अतिरिक्त मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, ब्रेल सूचना पट और आरओ वाटर फिल्टर शामिल हैं। ऊपरी बर्थ में कुशन के अलावा सभी

विरोध ► राजनीतिक दुर्भावना का आरोप लगाकर शून्यकाल कराया ठप

अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पर कांग्रेस ने किया रास में हंगामा

सीबीआइ और ईडी की कार्रवाई तेज होने से भड़की पार्टी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों पर सीबीआइ और ईडी की कार्रवाई तेज होने से भड़की पार्टी ने इस मुद्दे पर गृज्यसभा में सोमवार को जमकर हंगामा किया। पार्टी ने सरकार पर सीबीआइ और ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत कांग्रेस नेताओं को ही निशाना बनाया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ ईडी की जांच के गति पकड़ने और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जमीन आवंटन मामले में सीबीआइ के मुकदमा दर्ज करने के मद्देनजर कांग्रेस ने



इस मुद्दे को उठाया। गृज्यसभा में शून्यकाल की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सीबीआइ और ईडी की कार्रवाइयों को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित करार दिया। शर्मा ने वीरभद्र और हुड्डा के मामले का सीधे जिक्र

नहीं करते हुए कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ केंद्र सरकार सीबीआइ और ईडी को हथियार बना रही है। शर्मा की इस टिप्पणी का सत्ताधारी भाजपा के सदस्यों ने विरोध किया और हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस



नई दिल्ली में सोमवार को मेट्रो में सफर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेते आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल।

मोदी के कूटनीतिक अंदाज के कायल हुए टर्नबुल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विश्व नेताओं से रूबरू होने में निजी गर्माहट दिखाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज कूटनीतिक रितियों में नए आयाम लाने का जर्निया बनने लगा है। भारत दौर पर आए आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल के साथ मेट्रो से अक्षरधाम मंदिर का दर्शन और सैर करग कर मोदी ने विदेशी मेहमान को अपना मुरीद बना लिया।

कूटनीति की दुनिया में अहम विश्व नेताओं से निजी केमैस्ट्री विकसित करने के लिहाज से मोदी प्रोटोकॉल को अपने हिसाब से लचीला बनाने से नहीं हिचकते। इसी के तहत उन्होंने टर्नबुल

आर्थिक सहयोग समझौते पर फिलहाल नहीं बनी बात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक में आर्थिक सहयोग समझौते पर काफी अच्छी बातचीत हुई है लेकिन मामला आस्ट्रेलिया से कृषि से जुड़े उत्पादों के निर्यात को लेकर अटकाल हुआ है। आस्ट्रेलिया अनाज उत्पादन के साथ ही दुनिया का एक बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भी है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश होने की वजह से भारत नहीं चाहता कि उसका बाजार आस्ट्रेलियाई कृषि उत्पादों से भर जाए। भारत के संशय की एक वजह यह भी है कि अभी पूरी दुनिया में उदारवादी व्यापार समझौतों को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। कृषि उत्पादों की वजह से ही आस्ट्रेलिया और चीन के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते पर बात अटक गई है। बहल्लाल, सोमवार की वार्ता के बाद मोदी और टर्नबुल ने अपने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि समग्र आर्थिक सहयोग समझौते को वरीयता से लिया जाए। इस बारे में सवाल पूछने पर मोदी ने सकारात्मक जवाब दिया, ‘हमने फैसला किया है कि सीईएसए पर जल्द ही बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी।’

के साथ मेट्रो से सफर कर उन्हें अपना कायल बनाया। आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को अपने

प्रशंसकों में शामिल करना मोदी के लिए इस लिहाज से भी मायने रखता है कि टर्नबुल अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अब तक भारत से रिशतों में गर्मजोशी दिखाने में पीछे रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के डेढ़ साल बाद टर्नबुल भारत यात्रा पर आए हैं और इससे पहले उनका फोकस अमेरिका और चीन पर था। जबकि कूटनीति, व्यापार और रणनीति हर लिहाज से आस्ट्रेलिया की जितनी जरूरत भारत को है, उतनी ही आस्ट्रेलिया को भारत की। तभी मोदी ने निजी संवादों में गर्माहट से नहीं हिचकते। इसी के तहत उन्होंने टर्नबुल

मंत्री की गैरमौजूदगी ने राज्यसभा में सरकार की कराई किरकिरी

नई दिल्ली, प्रे़द : गृज्यसभा में केंद्र सरकार को उस समय शर्मिंदगी झेलनी पड़ी जब सांसद द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के लिए संबंधित मंत्रालय के मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। सभापति हामिद अंसारी ने कहा, यह हाल के वर्षों में पहली बार पैदा हुई असामान्य स्थिति है।

मामला प्रश्नकाल का है जब कांग्रेस के महेंद्र सिंह माहग के सूचीबद्ध प्रश्न का उत्तर देने की बारी आई। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु व ध्वनि प्रदूषण से संबंधित सवाल का जवाब पर्यावरण मंत्री अनिल दवे को देना था। कुछ क्षणों के बाद जवाब न आने पर कांग्रेस के जयश्रम रमेश ने मंत्री की गैरमौजूदगी का मामला उठाया। कहा कि सवाल का जवाब देने के अवसर पर मंत्री दूसरी बार सदन से अनुपस्थित रहे हैं। इसके बाद दवे के स्थान पर मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जवाब देने के लिए गृज्यसभा में आए। पूर्व में वह पर्यावरण मंत्री रहे थे। उन्होंने समय से न आ पाने के लिए पक्ष से माफी मांगी। बताया कि लोकसभा में एक विधेयक पेश कर रहे थे, इसलिए उन्हें गृज्यसभा



में आने में विलंब हुआ। सभापति हामिद अंसारी ने कहा, यह सबसे ज्यादा असामान्य स्थिति है। जिस मंत्री से संबंधित सवाल पूछा जाए, उसकी सदन में मौजूद रहने की जिम्मेदारी है। इस बात का ध्यान संसदीय कार्य मंत्री भी रखें। बाद में उन्होंने मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर मुखातिब होकर कहा, पिछले दस साल के कार्यकाल में उन्होंने नहीं देखा है कि कोई मंत्री सूचीबद्ध सवाल का जवाब देने के लिए मौजूद नहीं रहा है। यह बहुत ज्यादा असामान्य स्थिति है। अपने जवाब में जावड़ेकर ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में कुल 680 मॉनीटरिंग स्टेशन हैं, जो वायु और ध्वनि प्रदूषण का स्तर मापते हैं।

सदस्य वेल में आकर सीबीआइ और ईडी के कथित दुरुपयोग को लेकर नारेबाजी करने लगे। उपसभापति पीजे कुरियन ने कांग्रेस सदस्यों को वापस जाने के लिए कहा मगर उन्होंने एक न सुनी। इस पर कुरियन के साथ कांग्रेस सदस्यों को तीखी नोक-झोंक भी हुई और उन्होंने सदन दस मिनट के लिए स्थगित कर दिया।

सदन की कार्रवाई दोबार शुरू हुई तो भी यही दृश्य जारी रहा और नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सीबीआइ व ईडी का इस्तेमाल कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के लिए तो खूब हो रहा है। मगर भाजपा शासित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हुई गड़बड़ियों की जांच की मांग टुकड़ा जा रही है।

हंगामे के बीच सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने जब हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो कांग्रेस सदस्यों ने जमकर शोर मचाया और सदन स्थगित कर दिया। इस तरह शून्यकाल सीबीआइ व ईडी के कथित दुरुपयोग के मसले पर नहीं चल पाया।

चिदंबरम ने पूछा, आरके नगर में वितरित धन काला था या श्वेत

नई दिल्ली, आइएनएस : पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सोमवार को सरकार से पूछा कि चेन्नई की आरके नगर विधानसभा सीट पर मतदाताओं को वितरित किया गया धन काला था या श्वेत? बता दें कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को रिश्वत बांटे जाने के आरोपों के बाद इस सीट पर 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव को रिविगर रात अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था। चुनाव आयोग ने अपनी जांच में पाया है कि तमिलनाडु की आरके नगर विधानसभा सीट पर राजनीतिक दलों और उनके शीर्ष नेताओं ने मतदाताओं को रिश्वत देने के नए-नए तरीके इस्तेमाल किए।

केंद्र की आलोचना करते हुए चिदंबरम ने ट्वीट किया कि अगर नोटबंदी के बाद भारत में कालाधन खत्म हो गया है तो आरके नगर में क्या श्वेतधन बांटा गया था? चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि आरके नगर में अब मतदान तब करया जाएगा जब मतदाताओं को वितरित की गई धनराशि और उपहारों का प्रभाव समय के साथ खत्म हो जाएगा। दरअसल, आयोग ने यह कदम आवश्यक विभाग के उस कथन के बाद उठाया है जिसमें कहा गया था कि अन्नाद्रमुक के वीके शशिकला गुट ने मतदाताओं को करीब 100 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की है।

वेंकैया ने कहा, चिदंबरम ही दे सकते हैं अपने सवाल का जवाब : पी. चिदंबरम के सवाल के जवाब में वेंकैया नायडू ने कहा कि कालोधन पर जवाब वही बेहतर दे सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कालाधन कांग्रेस शासनकाल में ही पैदा हुआ है। काले या श्वेत धन का प्रता तो जांच के बाद ही चल सकेगा। हालांकि, इस बारे में भी चिदंबरम ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि वह उसी क्षेत्र से आते हैं।

मोटर विधेयक लोस में पारित, संशोधन खारिज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दुर्घटना मुआवजा समेत अनेक मुद्दों पर विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए सरकार आखिर लोकसभा में मोटर वाहन संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित करने में कामयाब हो गई। अब इसे केवल गृज्यसभा की दीवार पर करना शेष है। सरकार के इशारों को देखते हुए लगता है, वह वहां भी इसे येन-केन-प्रकारेण पास कर लेगी।

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ज्यादातर वही बातें दोहराई, जो बिल पेश करते वक़्त कही थीं। दुर्घटना में मौत की स्थिति में पांच लाख रुपये का न्यूनतम मुआवजा एक माह के भीतर देने के प्रावधान पर उनका तर्क था कि पांच लाख से संतुष्ट न होने वाले पीड़ितों के लिए ज्यादा मुआवजा पाने को मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल जाने का रास्ता खुला रहेगा। हालांकि माना जा रहा है कि ज्यादातर पीड़ित बीमा कंपनियों के दबाव में झंझट से बचने के लिए दुर्घटना के बाद की मानसिक स्थिति में पांच लाख के त्वरित मुआवजे पर राजी हो जाएंगे और मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल या अदालत पीड़ित की आर्थिक स्थिति के अनुसार मुआवजे का निर्धारण करती हैं और तदनुसार कभी-कभी पच्चीस या पचास लाख अथवा करोड़-दो करोड़ का मुआवजा भी देना तय कर देती हैं।

गृज्यसभा में अड़ सकता है विपक्ष : इसी आधार पर न्यूनतम मुआवजे की सीमा को 20 लाख किए जाने के लिए माकपा सांसद शंकर प्रसाद दत्ता ने संशोधन भी पेश किया था। लेकिन वोटिंग में वह 37 के मुकाबले 221 मतों से रद्द हो गया। गडकरी ने कहा कि मुआवजे को

20 लाख करने पर इंशुरेंस प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। कई विशेषज्ञ और विपक्षी दल इससे सहमत नहीं हैं और वे गृज्यसभा में संशोधन पर अड़ सकते हैं। गृज्यसभा में सरकार बहुमत में नहीं है।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना : विधेयक में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने के अलावा दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले भले लोगों की सुख्खा करने व उन्हें पुलिस के उल्पीड़न से बचाने तथा घटिया व त्रुटिपूर्ण वाहन बनाने वाले निर्माताओं की जवाबदेही तय करने जैसे नए प्रावधान हैं। गडकरी के मुताबिक, बिल का बुनियादी मकसद मानव जीवन को रक्षा करना है। क्योंकि हर साल पांच लाख सड़क दुर्घटनाओं में डेढ़ लाख लोग मारे जाते हैं। ‘जब भाजपा सरकार पांच साल पूरे करने तो सड़क हादसों से मरने वालों की संख्या आधी रह जाए, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।’

तो आरटीओ के खिलाफ होगी कार्रवाई : बिल में ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे प्रपत्रों को पूरी तरह ऑनलाइन कर पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है।

इसमें पात्र आवेदकों को परेशान करने और समय पर सर्टिफिकेट न देने वाले अफसरों को दंडित करने की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को लाइसेंस प्रदाता अधिकारी के पास सलाख पड़ेगा और यदि तीन दिन में लाइसेंस नहीं मिलता है तो आरटीओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। लॉनर लाइसेंस घर बैठे ऑनलाइन मिलेगा।

गडकरी ने कहा कि हादसों पर अंकुरा लगाने के लिए एक मंत्रालय सड़कों के किनारे क्रेश बैरियर लगाने की योजना बना रहा है। देश भर में दामा सेटर स्थापित करने का प्रस्ताव भी सरकार को प्राप्त हुआ है।

आधार से नहीं मारी जाएगी किसी गरीब की सब्सिडी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आधार को लागू किए जाने से किसी भी गरीब को मिलने वाली सब्सिडी नहीं मारी जाएगी। उन्होंने आंकड़ों की सुख्खा का भरोसा दिलाया। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि आधार व्यवस्था लागू होने से सिर्फ एलपीजी सब्सिडी में ही सरकार को 50 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है। गृज्यसभा में आधार को लेकर हुई अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मिड डे मील हो या कोई और योजना, किसी योग्य पात्र को सरकारी योजना से दूर नहीं रखा जाएगा। विश्व बैंक से लेकर संयुक्त रा्ट् की एजेंसियां तक कह रही हैं कि भारत ने आधार के रूप में अभूतपूर्व तकनीकी क्रांति की है। अब दुनिया भर के देशों को इसे अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर संपन्न के दौरान ही इसे शुरू किया गया, लेकिन इसमें सुधार के बाद इस अच्छे नतीजे दिखाई दे रहे हैं। प्रसाद ने कहा कि आधार के लिए आंकड़े लेने, उनकी

बोले रविशंकर

► **संसद में विपक्ष के सवालों पर दिया डाटा सुख्खा का भरोसा**

► **बोले, एलपीजी सब्सिडी में सरकार को 50 हजार करोड़ रुपये की बचत**

प्रोसेसिंग, स्टोर और उपयोग को लेकर नियम बना दिए गए हैं। इनका उल्लंघन करने वालों के लिए बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं।

कांग्रेस सांसद जयरम रमेश ने कहा कि आधार का उपयोग कहा अनिवार्य किया जा सकता है, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट दिशा-निर्देश होने के बावजूद सरकार इसका उल्लंघन कर रही है। सरकार सब्सिडी की बचत की बात कह रही है, लेकिन यह नहीं बता रही कि कितने को योग्य होने के बावजूद इस आधार पर सब्सिडी से वंचित होना पड़ा है। सांसद राजीव चंद्रशेखर ने पूछा कि 2016 में कानून पारित होने के पहले जमा किए सौ करोड़ लोगों के आंकड़ों की पुष्टि की क्या व्यवस्था है।

हमारी उपलब्धियों में एक और इज़ाफ़ा

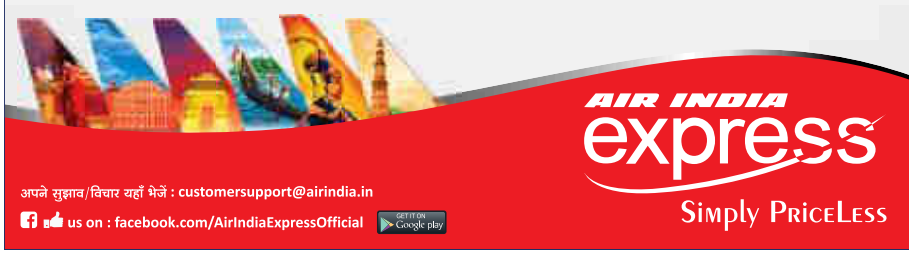


एयर इंडिया एक्सप्रेस ने प्राप्त किया आइओएसए रेजिस्ट्रेशन

एयर इंडिया के किफ़ायती विभाग, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने प्रतिष्ठित आइओएसए (आइएटीए ऑपरेशन सेफ्टी ऑडिट) रेजिस्ट्रेशन प्राप्त किया। यह पंजीयन उच्चतम एयरलाइन सुरक्षा स्तरों, कार्यकारी प्रबंधन और नियंत्रण प्रणालियों के लिये सख़्त ऑडिट के बाद प्रदान किया जाता है।

हमने वित्त वर्ष 2016-17 में 35 लाख से भी ज़्यादा यात्रियों को उनकी मंज़िलों तक पहुंचाया है। वर्तमान में, हम 15 भारतीय शहरों और मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के 14 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों से हर सप्ताह 550 से भी ज़्यादा प्रस्थान संपन्न करते हैं।

आकर्षक दरों पर अपनी टिकट्स बुक करें: **www.airindiaexpress.in** देखें 24x7 कॉल करें : **+91-44-30012001**



कुलभूषण जाधव के मुंबई स्थित घर पर सन्नाटा

आमप्रकाश तिवारी, मुंबई

कुलभूषण जाधव के महानगर स्थित घर पर सन्नाटा पसरा है। रिश्तेदारों- परिचितों का आना-जाना लगा है। सभी की आँखें नम हैं। लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जाने-माने वकील उज्ज्वल निकम का कहना है कि भारत को यह मामला अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहिए।

दोपहर बाद जैसे ही कुलभूषण को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाए जाने की खबर आनी शुरू हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओबी वैनस यहां उनके घर के बाहर जमा होना शुरू हो गईं। कुलभूषण का परिवार पवई उपनगर के पांश हीरानंदानी गार्डस इलाके की सिल्वर ओक इमारत में रहता है। कुलभूषण के पिता सुधीर जाधव ने सिल्वर ओक इमारत की बी-विंग स्थित पांचवीं मंजिल का 502 नंबर फ्लैट पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद खरीदा था। कुलभूषण को फांसी की सजा की खबर आने के बाद इमारत के बाहर पुलिस सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इमारत के

अंदर किसी अपरिचित को जाने नहीं दिया जा रहा है। कुलभूषण का परिवार मूलतः महाराष्ट्र के सतारा जनपद का रहने वाला है। उनके पिता सुधीर जाधव और चाचा सुभाष जाधव मुंबई पुलिस में सहायक पुलिस आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।

मुंबई आतंकी हमले (26/11) मामले में सरकारी वकील रहे उज्ज्वल निकम कहते हैं, भारत को यह मामला तुरंत अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहिए क्योंकि कुलभूषण को फांसी की सजा मिलने का कोई कारण पाकिस्तान सिद्ध नहीं कर सकता। कुलभूषण पर पाकिस्तान में कोई आतंकी वारदात अंजाम देने का आरोप नहीं है। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद वह किसी प्रकार की सरकारी सेवा में भी नहीं थे। उन्हें पाकिस्तान के किसी हिस्से से गिरफ्तार किया जाना भी साबित नहीं हुआ है। कुलभूषण को यह सजा सुनाने से पहले कानूनी सहायता भी नहीं दी गई। जबकि मुंबई पर आतंकी हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को भारत ने उसके पूरे मुकदमे के दौरान वकील उपलब्ध कराया था।

कव क्या हुआ

24 मार्च, 2016 : पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार करने की घोषणा की। हालांकि, पकड़े जाने की खबरें तीन मार्च को ही मिल गई थी।

26 मार्च, 2016 : पाकिस्तान के विदेश विभाग ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया और बयान जारी किया। कथित रूप से जाधव के गैरकानूनी रूप से प्रवेश और विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल होने पर विरोध जताया।

26 मार्च, 2016 : भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि जाधव का सरकार से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने समय से पहले ही नौसेना से रिटायरमेंट ले ली थी और अपना व्यापार कर रहे थे।

29 मार्च, 2016 : जाधव के इकबालिया बयान का एक वीडियो पाकिस्तान ने जारी किया। इसमें उनको यह कहते हुए देखा जा सकता है कि वह भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं और रॉ के लिए काम करते हैं। भारत ने इसकी प्रमाणिकता पर सवाल खड़े किए। करीब छह मिनट के वीडियो में लगभग सौ कट थे।

मार्च 2016 : इस्लामाबाद दौरे पर गए ईरान के

राष्ट्रपति हसन रूहानी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ से भारतीय जासूस की गिरफ्तारी के बारे में भी बातचीत होने से इन्कार किया।

अप्रैल 2016 : पाकिस्तान में जर्मनी के राजदूत रहे डॉ. गुंटर मुलक के अनुसार, जाधव को तालिबान ने पकड़ा और बाद में उसे आइएसआइ के हाथों बेच दिया।

अप्रैल 2016 : बलूचिस्तान की सरकार ने जाधव के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। इसमें आतंकवाद और विध्वंस के आरोप लगाए गए।

सात दिसंबर, 2016 : पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरतान अजीज ने सीनेट की एक समिति से कहा कि जाधव पर दिया गया डॉजियर केवल कुछ बयान भर हैं। उस पर पर्याप्त सबूत नहीं दिए गए हैं।

तीन मार्च, 2017 : पाकिस्तानी सीनेट को संबोधित करते हुए सरतान अजीज ने कहा कि जाधव को किसी भी हालत में भारत को नहीं सौंपा जाएगा।

चार अप्रैल, 2017 : एक गुप्त सुनवाई में जाधव को मौत की सजा सुनाई गई।

शताब्दी वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने किया सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह का आह्वान

चंपारण सत्याग्रह से निकला ‘पंचामृत’

गांधी की तुलना बाल कृष्ण से की, एक सुदर्शन चक्रधारी तो दूसरा चरखाधारी था

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से ‘पंचामृत’ की धारा निकली, जिससे देश के जन-जन को अपनी ताकत का अहसास हुआ। चंपारण सत्याग्रह के सौ साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय अभिलेखागार में आयोजित समारोह में उक्त बातें कहीं। सात दशक बाद भी गांधी के गंदगी मुक्त भारत का सपना पूरा न होने पर चिंता जताते हुए सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह के लिए लोगों का आह्वान किया।

चंपारण सत्याग्रह के पंचामृत के बारे में मोदी ने कहा कि गांधी ने लोगों को सत्याग्रह की ताकत और जनशक्ति से अवगत करया। स्वच्छता व शिक्षा के प्रति लोगों को जागृत किया। महिला सशक्तीकरण के साथ लोगों को खुद के हाथों से तैयार वस्त्रों को पहनना सिखाया। प्रधानमंत्री ने मोहनदास करमचंद गांधी की तुलना बाल मोहन कृष्ण से की। एक सुदर्शन चक्रधारी तो दूसरा चरखाधारी था। कृष्ण ने मुंह खोलकर मां यशोदा को ब्रह्मांड दिखाकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया तो महात्मा गांधी ने गुलामी से मुक्ति का रास्ता दिखा दिया। इससे पूर्व राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक रघुवर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंग वस्त्रम पहनाकर उनका स्वागत किया। संस्कृति व पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने



नई दिल्ली में सोमवार को राष्ट्रीय अभिलेखागार में चंपारण सत्याग्रह पर लगाई गई प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। प्रे

स्वागत भाषण दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गांधी ने सत्याग्रह और स्वच्छाग्रह एक साथ शुरू किया था, जिसमें सत्याग्रह से आजादी तो मिल गई, लेकिन स्वच्छ भारत का उनका सपना पूरा नहीं हो सका। एक सौ साल बाद भी उनका यह सपना अधूरा है। अब हमें मिलकर उसे पूरा करना है। हालांकि स्वच्छ भारत मिशन के जरिये बापू के सपने को पूरा करने को लोगों ने आंदोलन बना दिया है। तभी तो ढाई साल की अवधि में ही ग्रामीण भारत में जहाँ सिर्फ 42 फीसद लोग

ही शौचालयों का उपयोग करते थे, वह बढ़कर अब 63 फीसद हो गया है। 130 जिलों और 1.80 लाख गांवों ने खुद को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर लिया है। ग्रन्वों के नहीं हो सका। एक सौ साल बाद भी उनका यह सपना अधूरा है। अब हमें मिलकर उसे पूरा करना है। हालांकि स्वच्छ भारत मिशन के जरिये बापू के सपने को पूरा करने को लोगों ने आंदोलन बना दिया है। तभी तो ढाई साल की अवधि में ही ग्रामीण भारत में जहाँ सिर्फ 42 फीसद लोग

में स्वच्छता को शामिल किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि स्वच्छता के लिए कार्य करना ही महात्मा गांधी को सच्ची कार्याजलि होगी। गरीबों के कल्याण के लिए गंदगी मुक्त करना ही उपाय है। गंदगी मुक्त होने से ही गरीबों का हिमाचल प्रदेश और केरल ओडीएफ हो चुके हैं, जबकि गुजरात, हरियाणा और उत्तराखंड जल्द ही ओडीएफ होने की ओर हैं। गंगा किनारे के 75 फीसद गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने में सफलता मिल चुकी है। स्कूली पाठ्यक्रमों

में स्वच्छता को शामिल किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि स्वच्छता के लिए कार्य करना ही महात्मा गांधी को सच्ची कार्याजलि होगी। गरीबों के कल्याण के लिए गंदगी मुक्त करना ही उपाय है। गंदगी मुक्त होने से ही गरीबों का हिमाचल प्रदेश और केरल ओडीएफ हो चुके हैं, जबकि गुजरात, हरियाणा और उत्तराखंड जल्द ही ओडीएफ होने की ओर हैं। गंगा किनारे के 75 फीसद गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने में सफलता मिल चुकी है। स्कूली पाठ्यक्रमों

नहीं चलेगा एकतरफा संवाद



पटना में सोमवार को महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष पर दो दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य। प्रे

राज्य ब्यूरो, पटना

चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह की शुरुआत कर दिया और इसका कोई कारण नहीं बताया। इसके बाद उन्होंने रविवार को मुंबई से दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस पकड़ी। उस्मानाबाद के सांसद को विमान के बिजनेस क्लास से यात्रा करनी थी। संयोग है कि 23 मार्च को इसी उड़ान एआइ-852 में बिजनेस क्लास नहीं मिलने पर गायकवाड़ आया जो बैठे थे। उन्होंने एयरलाइन कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किया और एक विरिष्ट अधिकारी को सैडल से पीटा था। इसके बाद सांसद के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई और सभी भारतीय एयरलाइंस ने उनकी विमान यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। शिवसेना ने प्रतिबंध को लेकर संसद में हंगामा किया। पिछले सप्ताह

देश का एजेंडा क्या होगा? पर्यावरण पर भी बातें होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष में उनकी सरकार बापू के विचारों के साथ हर घर पर दस्तक देगी। स्कूलों में सुबक की प्रार्थना के बाद गांधी से जुड़ी एक कहानी सुनाई जाएगी। टोलों व गांवों में गांधी जी के विचारों पर आधारित फिल्में दिखाई जाएंगी। अगर 10 फीसद युवाओं ने भी गांधी जी के विचारों को आत्मसात कर लिया तो 10 से 15 वर्षों के भीतर समाज में बड़ा बदलाव आएगा। सरकार ने दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुुरीतियों के खिलाफ सशक्त अभियान चलाने का भी मन बना लिया है।

संविधान के खिलाफ है तीन तलाक

माला दीक्षित, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने एक बार फिर मुस्लिम महिलाओं के हक की तरफदारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मुसलमानों में प्रचलित तीन तलाक, बहुविवाह और हलाला से मुस्लिम महिलाओं को संविधान में मिले बराबरी के हक का हनन होता है। बराबरी के हक और महिलाओं की गरिमा से किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता। सरकार ने यह भी कहा है कि ये प्रथाएं मुस्लिम धर्म का अभिन्न अंग नहीं हैं। धार्मिक आजादी का अधिकार संविधान में मिले बराबरी और सम्मान से जीवन जीने के अधिकार के अधीन है। सरकार ने यह बातें तीन तलाक मामले में शीर्ष न्यायालय में दाखिल अपनों लिखित दलील में कही है।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 11 मई से तीन तलाक मामले पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने सभी पक्षों को दो सप्ताह में लिखित दलील दाखिल करने की छूट दी थी। अपनी दलील को आत्मसात कर लिया तो 10 से 15 वर्षों के भीतर समाज में बड़ा बदलाव आएगा। सरकार ने दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुुरीतियों के खिलाफ सशक्त अभियान चलाने का भी मन बना लिया है।

3.5 करोड़ महिलाएं तीन तलाक के पक्ष में

जागरण संवाददाता, जयपुर

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला शाखा ने एक बार फिर दोहराया है कि तीन तलाक मामले में किसी का भी हस्तक्षेप मंजूर नहीं होगा, फिर चाहे वह सरकार ही क्यों न हो। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए बोर्ड के दो दिवसीय सेमिनार में देशभर से आई करीब 20 हजार मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक के समर्थन में आवाज उठाई।

इस सम्मेलन में महिलाओं ने तलाक को कुरआन और शरीयत के अनुसार बताया गया और कहा कि इसके हक में देशभर से मुस्लिम महिलाओं से साढ़े तीन करोड़ फ़ार्म मिले हैं। सेमीनार (संगोष्ठी) के समापन के बाद महिला



भारत की जनसंख्या का आठ फीसद हिस्सा हैं (लगभग 96.68 मिलियन), सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ही असुरक्षित हैं। भले ही तीन तलाक या बहुविवाह से सीधे तौर पर कम महिलाएं प्रभावित होती हों, लेकिन यह भी सच है कि इस कानून की जद में आने वाली हर महिला हर समय इसके भय में जीती है, जिसका उसके स्तर, उसकी पसंद, उसके व्यवहार और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार पर दाखिल करने की छूट दी थी। अपनी दलील में सरकार ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं जो

शाखा की प्रमुख ऑफ़िसाइजर डॉ. अस्मा जहान ने प्रकराओं से कहा कि तीन तलाक पर किसी का भी अंगुली उठाना गलत है। शरीयत में शौहर के साथ बीवी को भी बराबर का हक दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब शौहर और बीवी का एक साथ रहना मुश्किल हो जाए तो उन्हें अलग होने का हक है। सेमिनार में तय किया गया कि राज्य का पहला शरिया कोर्ट जयपुर में स्थापित होगा।

लखनऊ की निकहत खान, दिल्ली की मसहूदा मजिद, मुरादाबाद की यूसूमिन और कानपुर की जाहिदा ने दावा किया कि देशभर में अन्य धर्मों के मुकाबले मुस्लिम समाज में तलाक के मामले कम हैं। सेमिनार में मेहर की रकम बढ़ाने पर जोर दिया गया।

शिया भी सुन्नी मुसलमानों के साथ

जागरण संवाददाता, लखनऊ : शिया समुदाय में तीन तलाक नहीं है। यह सिर्फ कुछ मुस्लिम मसलकों का मामला है। इसलिए शिया संगठनों को तीन तलाक पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सोमवार को चौक के इमामबाड़ा, गुफ्तनगनाबाव में मजलिस-ए-उलमा-ए-हिंद की कार्यकारिणी की बैठक में तीन तलाक का मामला उठा। बैठक में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व कश्मीर सहित कई प्रदेशों से आए उलमा ने तीन तलाक पर

बयानबाजी से बचने की सलाह दी। कहा कि भले ही तीन तलाक शियों में नहीं हैं, लेकिन शरीयत में बदलाव नहीं किया जा सका। इस मामले में हम सुन्नी मुसलमानों के साथ हैं। उलमा ने शिया समुदाय की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की। उलमा ने समुदाय के बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए

नेशनल न्यूज 5

<p>साए गए रतीय</p> <p>भूषण जाधव को के आरोप में फांसी नापाक पड़ोसी के इस ई है। यह पहला मौका से बदला लेने रतीय को साहस</p>		<p>किशोर भगवान</p> <p>फरवरी 2014 को भारतीय मछुआरे किशोर भगवान की पाकिस्तानी जेल में मौत की खबर आई। उनपर बिना किसी दस्तावेज पाकिस्तान के आर्थिक क्षेत्र में घुसने का आरोप लगाया गया। पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार किया। 2013 में किशोर ने वहां जेल से भागने की भी कोशिश की पर पकड़े गए। अज्ञात कारणों के चलते जेल में उनकी मौत हो गई।</p>	
<p>सरबजीत सिंह</p> <p>पंजाब के तरणताराण जिले के सरबजीत पर 1990 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बम धमाकों में शामिल होने का आरोप लगा। दरअसल वह धमाकों के दौरान गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान चले गए थे। वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने 1991 में उन्हें इस मामले में मौत की सजा सुनाई। भारत उनकी रिहाई के लिए प्रयास करता रहा। 2013 में लाहौर जेल में कैदियों से उनका झगड़ा हुआ। वह बुरी तरह घायल हुए जिसके बाद उनकी मौत हो गई।</p>		<p>चमेल सिंह</p> <p>जम्मू जिले के चमेल सिंह को पाकिस्तानी सेना ने 2008 में गिरफ्तार किया। उनपर जासूसी करने का आरोप लगा। उनके परिवार के मुताबिक खेतों में काम करने के दौरान उन्होंने गलती से सीमा पार कर ली थी। 2013 में लाहौर की जेल में पुलिसवालों की पिटाई से उनकी जान चली गई।</p>	

कोलभील ने बापू को बना दिया था महात्मा

सुनील राज, बेतिया

चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी कई कहानियां ऐसी हैं, जिनके साक्ष्य शायद इतिहास के पन्नों में न मिलें, मगर पढ़ियों से इलाके के लोग इसे सुनाते हैं। कहा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी मर्मस्पर्शी सच्चाइयों को देख बापू महात्मा बन गए। ऐसी ही एक सच्चाई यह थी कि यहां गरीबी इस हद तक थी कि महिलाओं के पास पुरा तन ढकने को भी कपड़े नहीं होते थे। वा ने जब बापू को इस सच्चाई से अवगत करया तब उन्होंने पूरे कपड़े त्याग करने का संकल्प लिया और तब से खुद से बुनी खादी की धोती और चादर से ही तन ढकते थे।

चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पहली बार 27 अप्रैल, 1917 को भित्तिहत्वा (पश्चिम चंपारण जिला, बिहार) आए थे। बिहार आए बापू किसानों की पीड़ा बताने के लिए गांव-गांव घूमते थे और उन्हें दस्तावेज की शक्ल देते थे। वे गांवों में जनसभाएं भी करते थे। भित्तिहत्वा आश्रम के सेवक अनिरुद्ध चौरसिया बताते हैं कि बापू जब गांवों में किसानों की समस्या सुनते थे तो हमेशा महसूस करते थे कि पीड़ा बताने वालों में महिलाओं की संख्या बेशक कम होती थी। जनसभाओं में भी ऐसा ही होता था। यह पहली बापू की समझ से परे थी। एक दिन दोपहर को महात्मा गांधी भित्तिहत्वा आश्रम के ढाई कोस पश्चिम में स्थित गांव कोलभील पहुंचे। यह गांव हड़बोड़ा नदी के किनारे बसा एक छोटा गांव है। बापू ने कहा कि तीन तलाक

में भ्रमण करने के दौरान बापू की नजर एक महिला पर पड़ी थी, जो काफी मैले-कुचैले कपड़े पहने हुए थीं। चौरसिया बताते हैं कि बापू ने उस महिला को देखने के बाद उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, पर आश्रम लौटने पर उन्होंने कस्तूरबा से यह बात बताई।

बापू ने बा(कस्तूरबा गांधी) से कहा कि उनकी जनसभाओं में भी जो महिलाएं आती हैं वे काफी गंदे कपड़े पहने होती हैं। जग पता करो इसकी वजह क्या है। बापू के कहने पर कस्तूरबा कोलभील गई और वहां उन्होंने एक महिला से गंदे रहने की वजह पूछी। कस्तूरबा के इस सवाल पर पहले तो वह महिला चुप रही। फिर उसने कस्तूरबा का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने घर के भीतर ले गईं। महिला ने अपनी एक लोहे की सटूकची खोल कर कस्तूरबा के सामने कर दी और सवाल किया आप बताएं मैं गंदी न रहू तो क्या करूं। मेरे पास सिर्फ यही एक धोती है, जिसका आधा हिस्सा धोकर शेष आधा हिस्सा पहने रहती हूं। मेरा काम ऐसे ही चलता है।

कस्तूरबा गांधी दुखी मन से कोलभील से भित्तिहत्वा आश्रमलौटीं और उन्होंने बापू के सामने साग सच रख दिया। बा के मुंह से वाक्या सुनने के बाद महात्मा गांधी ने उसी क्षण प्रण किया कि वे अब जीवन में पूरे कपड़े कभी धारण नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने पूरे कपड़े त्याग कर खादी से बनी एक धोती से अपना शरीर ढक लिया। उसी दिन बापू ने यह प्रण भी लिया कि वे चरखा कारीग्रे और अपने कपड़े खुद बुनेंगे तथा औरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।

अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण नहीं

सरकार ने तीन तलाक, हलाला और बहुविवाह प्रथा का विरोध करते हुए कहा है कि संविधान में सभी नागरिकों को अपने विश्वास और आस्था को मानने की आजादी दी गई है। लेकिन प्रत्येक प्रथा को इस आस्था और विश्वास का अभिन्न हिस्सा नहीं कहा जा सकता। धार्मिक प्रथा हर हाल में संविधान में दिए गए लैंगिक समानता, लैंगिक न्याय और गरिमा से जीवन जीने के संवैधानिक उद्देश्य को संतुष्ट करने वाली होनी चाहिए। तीन तलाक, बहु विवाह, हलाला को धर्म का जरूरी हिस्सा नहीं कहा जा सकता। इसलिए इन्हें अनुच्छेद 25 (धार्मिक आजादी) के तहत स्वतः संरक्षण नहीं मिल सकता।

के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, लेकिन इससे कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करने से रेंका नहीं जा सकता। **बाई ने अनचाही प्रथा कहा :** सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हलफनामे का हल्ला देते हुए कहा कि बोर्ड ने स्वयं उसमें इन्हें अनचाही प्रथाएं कहा है। किसी भी अनचाहे उसके स्तर, उसकी पसंद, उसके व्यवहार और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार पर दाखिल करने की छूट दी थी। अपनी दलील में सरकार ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को

अंतरराष्ट्रीय समझौतों से भी तुलना की है। कहा है कि तीन तलाक, हलाला और बहुविवाह प्रथा को अनुच्छेद 25 का संरक्षण नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 25 (धार्मिक आजादी) का अधिकार संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों विशेषकर बराबरी और सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार के अधीन है। पर्सनल ला को अनुच्छेद 13 के तहत कानून माना जाएगा। सरकार ने कहा है कि ये प्रचलन भारत के अंतरराष्ट्रीय संधियों के दायित्वों के अनुरूप नहीं है।

गाजियाबाद में पति को थाने में दिया तलाक

हसीन शाह, गाजियाबाद: देश भर में तीन तलाक को लेकर छिड़ी बहस के बीच मुगदनगर की एक महिला ने थाने में पुलिस के समक्ष ही पति को तीन बार तलाक कह दिया। पति ने शरीयत का हवाला देते हुए इस तलाक को अस्वीकार कर दिया और पत्नी को धर्मगुरुओं से सलाह लेने की नसीहत दी। पत्नी ने थाने में शिकायत कर इस तलाक को मान्यता देने की गुहार लगाई है।

कोट कालोनी निवासी नूरजाह को शादी 15 वर्ष पूर्व मेरठ में मुज्जेकोपुर गांव निवासी आशु के साथ हुई थी। शादी से पूर्व ही नूरजाह के माता-पिता की मृत्यु हो गई थी। आशु कारपेंटर है। अब उनके दो बच्चे हैं। शादी के बाद से ही आशु ने नूरजाह को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोप है कि वह प्रतिदिन शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता और उसे खर्च के लिए पैसे भी नहीं देता था। पीड़िता घर में ही कपड़ों को खिलाई कर घर का खर्च चला रही है। एक वर्ष पूर्व पति ने उस पर चाकू से वार कर दिया था, जिसके बाद उसने पारतपुर थाने में पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। सात माह पूर्व आरोपी आशु पत्नी और दोनों बच्चों को मुगदनगर ले आया और ईदगाह कालोनी में किराये के मकान में रहने लगा। शनिवार को नूरजाह किसी रिश्तेदार की शादी में गई थी। रात 11 बजे घर लौटी तो पति ने मकान की कुंडी खोलने से इन्कार कर दिया।

न्यूज गेलरी

विमान यात्रा के लिए आधार अनिवार्य करने पर विचार

नई दिल्ली : सस्कार घरेलू विमान यात्रा टिकटों के लिए आधार या पासपोर्ट को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। दुर्व्यलेहार के चलते विमान यात्रा से रूके गए लोगों का पता लगाने में यह उपयोगी साबित होा। नागरिक उड्डयन सचिव आरएन चौबे ने बताया कि विमानन रगुलेटर डीजीसीए इस सप्ताह नागरिक उड्डयन अनिवार्यता (सीएआर) पर काम शुरू करेगा। मंत्रालय ने डीजीसीए को इस मामले में सभी हितधारकों से चर्चा कर सीएआर का मसौदा तैयार करने को कहा है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने शनिवार को ट्वीट कर बेलगाम यात्रियों को मंथीर परिणाम की चेतावनी दी थी। इसमें पुलिस कार्रवाई और उड़ान से वंचित किए जाने वालों की सूची में डालना शामिल है। एयर इंडिया ने शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ द्वारा अपने कर्मचारी को सैडल को पीटे जाने वाले दिन ऐसी सूची का प्रस्ताव किया था। इसके दूसरे दिन जेट एयरवेज, स्पाइसजेट, इंडिगो और गोएयर के फंदेशान ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने भी ऐसे यात्रियों की सूची लागू करने का प्रस्ताव रखा था।

नशा तस्करी में कांग्रेस नेता को ढाई साल की कैद

भोपा : नशा तस्करी के एक मामले में नामजद पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के प्लानिंग व को-ऑर्डिनेशन सेल के जिला चेयरमैन सतपाल सत्ता ढुडीके को अतिरिक्त सेशन जज लखविंद कोर दुग्गल की अदालत ने सोमवार को ढाई वर्ष कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत के आदेश के अनुसार जुर्माना न देने की सूरत में आरोपी को छह माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। कांग्रेस नेता सतपाल सत्ता को अदालत ने बोते शुक्रवार को अफमी तस्करी के मामले में दोषी करार दिया था। अजीतवाल पुलिस ने 3 मार्च 2013 में सत्ता के स्कूटर से 500 ग्राम अफमी परामर्श की थी। सत्ता के खिलाफ एनपीपीएस एक्ट के तहत 3 मार्च 2013 को अजीतवाल थाने में एफआइआर दर्ज की गई दी। सतपाल इस मामले में जमानत पर था।

राखी सावंत की गिरफ्तारी के लिए दोबारा वारंट जारी

लुधियाना : भगवान श्री वाल्मीकि जी के बारे में अभद्र टिप्पणी के विवाद में फंसी अभिनेत्री राखी सावंत को फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभिनेत्री राखी सावंत के वकीलों द्वारा जिला एवं सेशन जज की कोर्ट में दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश दिनेश कुमार ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने राखी सावंत गिरफ्तारी के लिए दोबारा वारंट जारी करने के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी।

इससे पहले राखी सावंत के वकीलों ने कोर्ट से अंतिम जमानत मंजू कर देने का आग्रह किया। उन्होंने कोर्ट से कहा कि राखी सावंत ने किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई है। इसी दौरान शिकायतकर्ता वकील नरिंदर आह्ला को जज जमानत याचिका की भनक मिली तो वो भी साथी वकीलों के साथ कोर्ट में पहुंच गए। उन्होंने राखी की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राखी सावंत ने जानबूझ कर एक विपरीत समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

हरियाणा रोडवेज की चार हजार बसों के पहिये थमे

चंडीगढ़ : हरियाणा में निजी बसों को परमिट दिए जाने के खिलाफ सोमवार को रोडवेज कर्मचारियों ने अनिश्चितकाल के लिए बसों का चक्का जाम कर दिया। दोपहर बाद चंडीगढ़ में सरकार से वार्ता विफल होने की सूचना मिलते ही रोडवेज कर्मचारी चार हजार बसों को वर्कशॉप और बस अड्डों में खड़ा कर सड़कों पर उतर आए। अचानक हुई हड़ताल से जहां यात्रियों के पसीने छूट गए, वहीं निजी वाहन चालकों ने मौके का फायदा उठा जमकर चांदी कूटी। बता दें कि हरियाणा रोडवेज की बसें पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्यप्रदेश में भी जाती हैं। वैसे में बसों के नहीं चलने से दूसरे राज्यों में जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

चेतावनी

हिमालयी क्षेत्र की भूगर्भीय प्लेटों के लगातार तनाव में रहने के चलते उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में बड़े भूकंप की हर वक़्त बनी रहती है आशंका।



राजकीय सम्मान के साथ शहीदों को अंतिम विदाई

जागरण न्यूज नेटवर्क, रंची

जम्मू कश्मीर के लद्दाख स्थित बटालिक क्षेत्र में हिमस्खलन में दबकर शहीद हुए झारखंड के तीन सपरुतों के शव सोमवार को रंची पहुंचे। एयरपोर्ट से लांस नायक बिहारी मरांडी का शव पाकुड़ के हिरणपुर ले जाया गया। वहीं इटकी थाना क्षेत्र के सेमर निवासी जवान प्रभु सहाय तिकौी व मांडर थाना क्षेत्र के विसह खटंगा निवासी जवान कुलदीप लकड़ा का पार्थिव शरीर सोमवार शाम लगभग तीन बजे दोनों के गांव पहुंचा। रंची एयरपोर्ट पर शव पहुंचने की सूचना के बाद ही शहीदों के घरों में भीड़ जुटने लगी थी। पार्थिव शरीर पहुंचते ही पूरा गांव भारत माता की जय के नारों से गुंज उठी। राजकीय सम्मान के साथ तीनों का उनके गांवों में अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान पर्रिजनों समेत सैकड़ों आंखें नम दिखीं। सेना के लांस नायक बिहारी मरांडी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव हिरणपुर के रामनाथपुर में परंपरागत सनातन रीति रिवाज से किया गया। यहां मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम थीं। अंतिम दर्शन को भीड़ जुड़ पड़ी। इस दौरान शहीद बिहारी अमर रहे के जयघोष से गांव गुंजता रहा। बड़े भाई प्रधान मरांडी ने मुखामिन दी। बिहारी 21 बिहार रेजीमेंट के जवान थे। इससे पूर्व शहीद लांस नायक बिहारी मरांडी का पार्थिव शरीर दोपहर बाद करीब 3:30 बजे

कामयाबी

एलओसी सटै क्षेत्र में सेना ने घुसपैट का प्रयास किया नाकाम

जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में चार आतंकी ढेर

बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद व अन्य सामान बरामद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

सेना ने उत्तरी कश्मीर में एलओसी (निंत्रण रेखा) से सटे केरन सेक्टर में घुसपैट का प्रयास नाकाम बना लश्कर-ए-तैयबा के चार आतंकीयों को मार गिराया। मारे गए आतंकीयों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के अलावा जीपीएस्, रेडियो सेट व कुछ नक्शे मिले हैं।

जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में रविवार देर रात स्वचालित हथियारों से लैस आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे थे। वहां गश्त कर रहे सैन्यकर्मियों के एक दल ने उन्हें देख लिया। जवानों ने उसी समय निकटवर्ती सुरक्षा चौकियों को सूचित करते हुए पोजीशन ले ली। जैसे ही आतंकी पूरी रक्षा के घेरे में आ गया है। जम्मू-कश्मीर की जनता ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है।

ट्विट के जिएए रहलु गांधी ने कहा कि दशकों तक लगातार मेहनत के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास को बहाल किया गया था लेकिन भाजपा व पीडीपी की गठबंधन सरकार ने महज तीन वर्षों में सब कुछ खत्म कर दिया। लोकसभा उपचुनाव में महज सात फीसदी मतदान होना इसी बात को कश्मीर के लोगों के दौघन आट लोगों की हत्या भी राज्य की दयनीय स्थिति को दर्शा रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री महबूबा

कुछ खत्म कर दिया। लोकसभा उपचुनाव में महज सात फीसदी मतदान होना इसी बात को कश्मीर के लोगों के दौघन आट लोगों की हत्या भी राज्य की दयनीय स्थिति को दर्शा रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री महबूबा

रायपुर के होटल में भीषण आग, पांच कारोबारी जिंदा जले

नईदुनिया, रायपुर

शहर के रहमानिया चौक, बंजारा मार्केट में रविवार-सोमवार की रात होटल तुलसी में आग लग गई। एक घंटे के अंदर आग बेकाबू हो गई और उसने श्रांउड प्लेनर से लेकर 5वें माले को अपनी चपेट में ले लिया। होटल में 12 मुसाफिर (सभी कारोबारी) ठहरे हुए थे, जिनमें से पांच को बाहर आने का मौका ही नहीं मिल सका और वे जिंदा जल गए। बचे सात मुसाफिर और पांच होटल कर्मियों में किसी ने दूसरे माले से छलांग लगाई तो कोई जान बचाने पड़ोस की बिल्डिंग में जा आशंका है कि कुछ और शव हो सकते हैं।

घटना रविवार रात दो बजे की है। कारोबारी सुभाष सोनी के इस होटल में 42 कमरे हैं। घटना वाली रात 12 मुसाफिर सोए हुए थे। आग सूचना फापर ब्रिगेड को 3:05 बजे पहुंची और कुछ ही मिन्ट में दमकलकर्म मौके पर

बड़े खतरे का संकेत हो सकते हैं भूकंप के झटके

गढ़वाल में हाल में आए भूकंप

धमती के अंदर चल रही उथल-पुथल को लेकर धर्तरीनुमान व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके प्रति सचेत अवश्य रहने की जरूरत है। विशेषकर तब जबकि यह बता पाना असंभव हो कि किसी भी क्षेत्र में कब औरकितना बड़ा भूकंप कितनी अरवधि के भीतर आ सकता है। वैसे में चिंता बढ़ना अस्वाभाविक भी नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार उत्तराखंड में जिस प्रकार से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, वे बड़े खतरे का संकेत भी हो सकते हैं। वाडिग हिमालय भूविज्ञान संस्थान के विशेषज्ञों के अनुसार उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में बड़े भूकंप की आशंका हर वक़्त बनी रहती है। ये आने वाले दिनों से लेकर 50 साल बाद भी आ सकते हैं। हिमालयी क्षेत्र की भूगर्भीय प्लेटों का लगातार तनाव में रहना इसकी मुख्य वजह है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष 45 मिलीमीटर की रफ़्तार से यूरोशियन प्लेट के नीचे घुस रही है। इससे भूगर्भ में लगातार ऊर्जा संचित हो रही है। तनाव बढ़ने से निकलने वाली अत्यधिक ऊर्जा से भूगर्भीय चट्टानें फट सकती हैं। 2000 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला के हर 100 किमी क्षेत्र में उच्च

श्रद्धांजलि

रंची में प्रभु सहाय तिकौी और कुलदीप लकड़ा को दी गई मिट्टी

पाकुड़ में लांस नायक बिहारी मरांडी का हुआ अंतिम संस्कार

जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन में दबकर हुए थे शहीद

सेना के हेलीकॉप्टर से समाहरणालय के समीप हैलीपैड पर पहुंचा। यहां नायक सूवेदार विनोद कुमार के नेतृत्व में जवानों ने शहीद को सलामी दी। यहां से सिख रेजिमेंट के विनोद कुमार, एसएस सिंह समेत 15 जवान तिरंगे में लिपटे शहीद को लेकर करीब चार बजे रामनाथपुर पहुंचे।

उधर जवान प्रभु सहाय तिकौी को श्रद्धांजलि देने के लिए आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे थे। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। पांच दिनों से धैर्य रख रही मां विराजमणि का धैर्य टूट गया। उनके चोत्कार से माहौल और गमगीन हो गया, वहां मौजूद हर किसी के आंख से आंसू बह पड़े। पत्नी सुचिता तिकौी भी दहाड़ माखर रने लगी व रोते-रोते बेहोश हो गईं। दोनों पुत्र (अक्षय व अर्नीश) भी रो रहे थे। अंतिम यात्रा शाम चार बजे

अनंतनाग चुनाव रद होने पर महबूबा इस्तीफा दें : उमर

आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। आतंकीयों ने जवानों पर फायर करते हुए बापस गुलाम कश्मीर की तरफ भागना शुरू कर दिया। जवानों ने जवाबी फायर किया।

दोनों तरफ से करीब तीन घंटे तक गोलियां चलीं। सोमवार सुबह सू्योदय के बाद जब जवानों ने मुठभेड़स्थल की तलाशी ली तो उन्हें वहां गोлияं से छलनी चार आतंकीयों के शव मिले।

जवानों ने चारों शव व उनसे मिले हथियार और अन्य सामान को कब्जे में ले लिया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने कहा कि मारे गए आतंकीयों की पहचान की जा रही है। वे पाकिस्तान मूल के लश्कर आतंकी हैं। मुठभेड़स्थल पर खून के कुछ धब्बे भी मिले हैं जो गुलाम कश्मीर की तरफ जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि मारे गए आतंकीयों के एक या दो साथी जखमी हैं और वे सरहद पार भागने में कामयाब रहे हैं। पूरे इलाके में जवानों ने सघन तरह तलाशी अभियान जारी रखा हुआ है।

मोदी की कश्मीर पालिसी फेल : राहुल

नई दिल्ली, प्रे़ : कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर पालिसी पूरी तरह से फेल साबित हुई है। इसके साथ ही भाजपा व पीडीपी गठबंधन भी सवालों के घेरे में आ गया है। जम्मू-कश्मीर की जनता ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है।

ट्विट के जिएए रहलु गांधी ने कहा कि दशकों तक लगातार मेहनत के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास को बहाल किया गया था लेकिन भाजपा व पीडीपी की गठबंधन सरकार ने महज तीन वर्षों में सब

द बर्निंग होटल

होटल से शव बरामद करने में 12 घंटे लगे, 20 घंटे चला रेस्क्यू

होटल स्टाफ भागा, कमरों में सोए मुसाफिर फंसे रह गए

पहुंचकर रेस्क्यू में जुट गए। फायर अमले ने अंदर से चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनीं, लेकिन होटल से निकलती आग की लपटों और धुएं के कारण फायरमैन के लिए अंदर कदम रखना नामुमकिन था। सुबह पांच बजे के करीब फायरमैन अंदर दाखिल हो सके। दोपहर एक बजे पहला शव निकाला जा सका। बता दें कि मुसाफिर मुंबई, गुजरात, नागपुर के रहने वाले थे, जो कारोबार के सिलसिले में रायपुर आए थे। कई शवों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है।

खिड़की पर ही हो गई मौत : आग लगने के बाद मुसाफिरों में अफस-तफरी मच गई। जान बचाने के लिए उन्होंने भागने की

इलाहबाद : सैम हिंगइन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (शियाट्स)में 'जन गण मन' या वंदेमातृस की मांग पर शोधछात्र अभय गोस्वामी को निर्लंबित कर दिया गया। छात्र ने गत सप्ताह परिसर में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में किसी एक को अनिवार्य कराने की मांग थी।

राजकीय सम्मान के साथ शहीदों को अंतिम विदाई



जम्मू कश्मीर के बटालिक सेक्टर में हिमस्खलन में शहीद हुए लांस नायक बिहारी मरांडी के पार्थिव शरीर के उनके गांव पाकुड़ जिले के रामनाथपुर पहुंचने पर परिजनों की रीत्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया।

रवाना हुई। अंतिम मिट्टी स्थानीय कब्रिस्तान में ईसाई रीति-रिवाज से दी गई। इन् बीच कुलदीप लकड़ा का पार्थिव शरीर के उनके गांव पाकुड़ जिले के रामनाथपुर पहुंचने पर परिजनों की रीत्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया।

रवाना हुई। अंतिम मिट्टी स्थानीय कब्रिस्तान में ईसाई रीति-रिवाज से दी गई। इन् बीच कुलदीप लकड़ा का पार्थिव शरीर के उनके गांव पाकुड़ जिले के रामनाथपुर पहुंचने पर परिजनों की रीत्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया।

अनंतनाग चुनाव रद होने पर महबूबा इस्तीफा दें : उमर

राज्य ब्यूरो, जम्मू : अनंतनाग संसदीय सीट के लिए उपचुनाव रद करने की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पेशकश पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो महबूबा मुफ्ती इस्तीफा दें और राज्यपाल कामकाज संभाल लें। भाजपा-पीडीपी ने कश्मीर को तोहमत लगा दी है। चुनाव टालने के तसद्दुक मुफ्ती के बयान पर उमर ने कहा कि इससे पता चलता है कि उनकी बहन महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह नाकाम हो गई है। भाजपा को यह क्यों नहीं दिख रहा है। कश्मीर के हालात लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए किसी भी तरह से सही नहीं हैं। सुलग रहे कश्मीर में आपका स्वागत है। सरकार को घेरते हुए उमर ने सोमवार को सोशल साइट ट्विटर पर लिखा कि केंद्र सरकार को कुछ लेना-देना नहीं है। राज्य सरकार कुछ भी करने में लाचार है

जम्मू एवं कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पैंलेट गन पर रोक लगाने की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल मुकुल रहैतगी ने कहा कि सुरक्षा बल कम से कम बल का प्रयोग करते हैं ताकि जन धन की हानि न हो। जब प्रदर्शनकारी उनके बिल्कुल करीब आ जाते हैं तब वे आखिरी विकल्प के रूप में पैंलेट गन का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि रविवार को कश्मीर में उपचुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। यह कोई आम प्रदर्शनकारी नहीं हैं जिन पर आसानी से काबू पाया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए नया स्टैन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बनाया गया है। नए एसओपी में पैंलेट गन से पहले रबर की गोलियां प्रयोग की जाती हैं। इन दलौलों पर कोर्ट ने याची बार एसोसिएशन से केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करते हुए कोई विकल्प बताने को कहा। वह कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें पैंलेट गन का

मुफ्ती को तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। उनका कहना है कि लोकसभा उप चुनाव को पारदर्शी तरीके से कराने के लिटमस टेस्ट में राज्य सरकार फ्लाप साबित हुई हैं। उनका कहना है कि सात फीसदी मतदान दर्शा रहा है कि लोगों ने गठबंधन सरकार को पूरी तरह से नकार दिया है। कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव ने संसद के बाहर पत्रकारों से कहा कि लोगों ने सरकार के खिलाफ दशकों से प्रस्ताव दिया है। उनका कहना था कि अगर पीएम मोदी की कोई कश्मीर पालिसी है तो वह बुरी तरह से फेल साबित हुई है।



रायपुर में सोमवार को होटल में आग लगने के बाद राहत कार्य में जुटे अग्निशमनकर्मी। नई दुनिया

कोशिश की, लेकिन धुएं की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कुछ चिचन की तरफ भागे, जहां खिड़की थी। एक कारोबारी का शव खिड़की से चिपका हुआ मिला।

उत्तराखंड में चार दिनों में दूसरी बार झटके

देहरादून : उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में चार दिनों के अंतराल में एक बार फिर भूकंप के झटकों से धरती डोला उठी। इस बार भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी जिले में था और झटके भी वहीं महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई। राज्य आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के अनुसार कहीं से भी किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। उत्तरकाशी जिले में भूकंप के झटके सोमवार को दोपहर दो बजकर 20 मिन्ट और 34 सेकंड पर महसूस किए गए।

बताया कि यूरोशियन-इंडो प्लेट की टकराहट से भूमि के भीतर से ऊर्जा बाहर निकलती रहती है। इससे भूकंप के झटके आते रहते हैं। हालांकि उत्तरखंड समेत समूचे उत्तर भारत में लंबे समय से बड़ा भूकंप नहीं आया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि यहां धरती के भीतर भारी मात्रा में ऊर्जा संकत हो सकती है, जो कभी भी बड़े भूकंप का सबब बन सकती है।

राजकीय सम्मान के साथ शहीदों को अंतिम विदाई



जम्मू कश्मीर के बटालिक सेक्टर में हिमस्खलन में शहीद हुए लांस नायक बिहारी मरांडी के पार्थिव शरीर के उनके गांव पाकुड़ जिले के रामनाथपुर पहुंचने पर परिजनों की रीत्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया।

रवाना हुई। अंतिम मिट्टी स्थानीय कब्रिस्तान में ईसाई रीति-रिवाज से दी गई। इन् बीच कुलदीप लकड़ा का पार्थिव शरीर के उनके गांव पाकुड़ जिले के रामनाथपुर पहुंचने पर परिजनों की रीत्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया।

रवाना हुई। अंतिम मिट्टी स्थानीय कब्रिस्तान में ईसाई रीति-रिवाज से दी गई। इन् बीच कुलदीप लकड़ा का पार्थिव शरीर के उनके गांव पाकुड़ जिले के रामनाथपुर पहुंचने पर परिजनों की रीत्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया।

अनंतनाग चुनाव रद होने पर महबूबा इस्तीफा दें : उमर

आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। आतंकीयों ने जवानों पर फायर करते हुए बापस गुलाम कश्मीर की तरफ भागना शुरू कर दिया। जवानों ने जवाबी फायर किया।

दोनों तरफ से करीब तीन घंटे तक गोलियां चलीं। सोमवार सुबह सू्योदय के बाद जब जवानों ने मुठभेड़स्थल की तलाशी ली तो उन्हें वहां गोлияं से छलनी चार आतंकीयों के शव मिले।

जवानों ने चारों शव व उनसे मिले हथियार और अन्य सामान को कब्जे में ले लिया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने कहा कि मारे गए आतंकीयों की पहचान की जा रही है। वे पाकिस्तान मूल के लश्कर आतंकी हैं। मुठभेड़स्थल पर खून के कुछ धब्बे भी मिले हैं जो गुलाम कश्मीर की तरफ जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि मारे गए आतंकीयों के एक या दो साथी जखमी हैं और वे सरहद पार भागने में कामयाब रहे हैं। पूरे इलाके में जवानों ने सघन तरह तलाशी अभियान जारी रखा हुआ है।

रायपुर के होटल में भीषण आग, पांच कारोबारी जिंदा जले

नईदुनिया, रायपुर

शहर के रहमानिया चौक, बंजारा मार्केट में रविवार-सोमवार की रात होटल तुलसी में आग लग गई। एक घंटे के अंदर आग बेकाबू हो गई और उसने श्रांउड प्लेनर से लेकर 5वें माले को अपनी चपेट में ले लिया। होटल में 12 मुसाफिर (सभी कारोबारी) ठहरे हुए थे, जिनमें से पांच को बाहर आने का मौका ही नहीं मिल सका और वे जिंदा जल गए। बचे सात मुसाफिर और पांच होटल कर्मियों में किसी ने दूसरे माले से छलांग लगाई तो कोई जान बचाने पड़ोस की बिल्डिंग में जा आशंका है कि कुछ और शव हो सकते हैं।

घटना रविवार रात दो बजे की है। कारोबारी सुभाष सोनी के इस होटल में 42 कमरे हैं। घटना वाली रात 12 मुसाफिर सोए हुए थे। आग सूचना फापर ब्रिगेड को 3:05 बजे पहुंची और कुछ ही मिन्ट में दमकलकर्म मौके पर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

जेलों के अंदर से चल रहे अपराध पर नियंत्रण की दिशा में कदम उठाते हुए योगी सरकार ने एक पखवारे के अंदर 51 शांति अपराधियों की जेल बदली है। सोमवार को प्रतापगढ़ जिला कारागार में निरुद्ध शांति अपराधी सतीश मिश्र उर्फ बालकृष्ण समेत आठ अपराधियों की जेल बदलने का आदेश जारी किया है। मुख्तार अंसारी और अलीक अहमद की जेल पहले ही बदली जा चुकी है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि झांसी जिला कारागार में निरुद्ध दस, प्रतापगढ़ जेल के आठ, गोरखपुर के सात, बाराबंकी जिला कारागार के छह बंदी और दोसरे जगहों से देखने वालों पर भी फायरिंग करते हैं और पेलेट गन चलाते हैं। जिससे वे लोग चपेट में आ जाते हैं।

योगी सरकार के स्टिंग में फंसे दो डॉक्टर

प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टरों पर कार्रवाई को लेकर थोड़ी सख्ती क्या हुई, खुद का नर्सिंगहोम और हॉस्पिटल बनाने वाले चिकित्सकों में खलबली मच गई। निजी प्रैक्टिस प्रभावित न हो, उसके लिए डाक्टरों ने सरकारी नौकरी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग से हुई।

पिछले दिनों किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस से बाज जाने की हिदायत दी थी। इसके बाद स्वास्थ्य महकमा तेजी से सक्रिय हुआ। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को साक्ष्यों के साथ पकड़ने के लिए स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। इस अभियान के पहले दौर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉ.आरएन यादव और राजकीय मेडिकल कॉलेज बांदा के मेडिसिन विभाग के चिकित्सक डॉ. कान राजभूत फंस गए। डॉ.यादव के स्टिंग का वीडियो अपर मुख्य

गाजियाबाद में विलक के नाम पर एक हजार करोड़ की ढगी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

वेबसाइट बनाकर सोशल ट्रेड कंपनी ने बीस हजार लोगों से करीब एक हजार करोड़ की ढगी की। कंपनी के डायरेक्टर व अन्य स्टाफ ऑफिस बंद कर फरार हैं। कंपनी द्वारा विलक के पैसेसिक बिजनेस पार्क में पे-वे आइटो सोल्युशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी गाय है। कंपनी ने विलक देने के लिए वेब पेज लाइव डॉटकॉम के नाम से साइट बनाई थी।5750 रुपये, 11500 रुपये, 57500 रुपये और 1,15000 रुपये में मंथर बनाए जाते थे। 5750 रुपये में प्रतिदिन 10 लाइक और प्रत्येक लाइक छह रुपये, 11500 रुपये में प्रतिदिन 20 लाइक और प्रति लाइक छह रुपये, 57500 रुपये में प्रतिदिन 100 लाइक और प्रति लाइक

अनुसार चिरंजीव विहार के रहने वाले कुछ लोगों ने 17 दिसंबर 2016 को साहिबाबाद के पैसेसिक बिजनेस पार्क में पे-वे आइटो सोल्युशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी खोली थी। कंपनी ने विलक देने के लिए वेब पेज लाइक डॉटकॉम के नाम से साइट बनाई थी।5750 रुपये, 11500 रुपये, 57500 रुपये और 1,15000 रुपये में मंथर बनाए जाते थे। 5750 रुपये में प्रतिदिन 10 लाइक और प्रत्येक लाइक छह रुपये, 11500 रुपये में प्रतिदिन 20 लाइक और प्रति लाइक छह रुपये, 57500 रुपये में प्रतिदिन 100 लाइक और प्रति लाइक

श्रीनगर उपचुनाव के बाद भी वादी में हिंसक झड़पें

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : श्रीनगर संसदीय सीट के उपचुनाव के दौरान रविवार को हुई हिंसा का असर सोमवार को भी नजर आया। पूरी वादी में बंद के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें करीब 12 लोग घायल हो गए। कट्टररफ़्थी सेवद अली शाह गिलानी के अलावा मीरवाइज मौलवी उमर फारूक समेत सभी प्रमुख अलगाववादियों को प्रशासन ने एहतियातन घरो में नजरबंद रखा। इसके साथ ब



दैनिक जागरण

अक्सर परेशानियों की वजह हम स्वयं होते हैं

एक और नापाक हरकत

पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाकर भारत से संबंध सुधार की रही-सही उम्मीदों पर पलीता लगाने का ही काम किया है। पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान की यह हरकत दोनों देशों के संबंधों को रसातल में ले जाने के मामले में एक तरह से ताबूत में आखिरी कील की तरह है। भारत उचित ही इस नतीजे पर पहुंचा कि पाकिस्तान कुलभूषण को छल-छद्म से हर हाल में सजा सुनाने पर आमादा था और यदि वह फ्रांसी की इस सजा पर अमल करता है तो इसे सुनियोजित हत्या माना जाएगा। पाकिस्तान ने पिछले वर्ष मार्च में जब कुलभूषण को बलुचिस्तान में सक्रिय रॉ एजेंट के तौर पर गिरफ्तार करने का दावा किया था तभी यह स्पष्ट हो गया था कि वह सनसनीखेज कहानी लेकर आया है। इसकी पुष्टि पाकिस्तान में कार्यरत रहे एक जर्मन राजनयिक ने यह कहकर की थी कि पाकिस्तानी सेना ने कुलभूषण जाधव को ईरान की सीमा से अगवा किया और फिर यह दिखा दिया कि उन्हें बलुचिस्तान से पकड़ा गया। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने कुलभूषण जाधव को रॉ का जासूस साबित करने की कोशिश में उनका एक वीडियो भी जारी किया था, लेकिन इससे कुल मिलाकर यही अधिक साबित हुआ कि उन्हें वीडियो का सही तरह संपादन करना भी नहीं आता। यह वीडियो उसी क्षण झूठ साबित हो गया था जब कुलभूषण जाधव यह कहते सुने गए थे कि वह नौसेना के सेवारत अधिकारी हैं। पाकिस्तान की पोल तब भी खुली थी जब पाकिस्तानी सेना की ओर से यह दावा किया गया था कि वह उनकी सेनाध्यक्ष ने इस्लामाबाद की यात्रा पर आए ईरान के राष्ट्रपति से कुलभूषण के मामले में बात की है। ईरानी राष्ट्रपति ने तत्काल ही ऐसी किसी बातचीत को बकवास करार दिया था। कुलभूषण के मामले में पाकिस्तान के मन का चोर तब भी बेकाब हुआ था जब उसने भारतीय अधिकारियों को उनसे संपर्क करने का अवसर नहीं दिया। भारत ने अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों का खाला देकर कुलभूषण जाधव से संपर्क करने की बार-बार मांग की, लेकिन पाकिस्तान हर बार कन्नी काट गया। पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तानी सेना के कपट की पोल खुद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेश मामलों के सलाहकार सत्ताज अजीज ने पाकिस्तानी संसद में यह कहकर खोली थी कि कुलभूषण के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। यह भी एक तथ्य है कि खुद पाकिस्तान में अनेक लोग यह मानते हैं कि कुलभूषण जाधव को अगवा कर उसे रॉ एजेंट इसलिए करार दिया गया, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत से संबंध सुधार की कोशिश रास नहीं आ रही थी। चूंकि अब नवाज शरीफ राजनीतिक रूप से और कमजोर हो चुके हैं इसलिए इसकी उम्मीद कम है कि वह अपनी ही सेना की गंदी हरकत के खिलाफ कुछ कर सकेंगे। ऐसे में यह और आवश्यक हो जाता है कि भारत सरकार कुलभूषण जाधव का हथ्र सबज्जीत जैसा न होने दे। इसके लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए। भारत को इस्लामाबाद ही नहीं, सारी दुनिया को यह संदेश देने की जरूरत है कि पाकिस्तान किसी भारतीय नागरिक से मनमानी नहीं कर सकता।

मुलाकात के मायने

करीब आठ माह बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को मुलाकात की। पिछले वर्ष आठ नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद से ममता ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। बार-बार कहती आ रही थीं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह कभी मोदी के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगी। परंतु बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौर के दौरान ममता को भी दिल्ली आमंत्रित किया गया था। ममता पिछले शुक्रवार से दिल्ली में हैं। हसीना व मोदी द्वारा शुरू की गई बस व ट्रेन सेवा के समारोह में भी ममता मौजूद रहीं। लगे हाथ सोमवार को ममता ने नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ली। दोनों नेताओं के बीच के करीब आधे घंटे तक राज्य में ऋण की स्थिति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इस दौरान बांग्लादेश की तीस्ता नदी जल समझौते पर कोई बात नहीं हुई। वार्ता के बाद ममता ने कहा कि हमने राज्य पर ऋण की स्थिति और विभिन्न परियोजनाओं के तहत राज्य के लिए वित्त के बारे में चर्चा की। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार के पास राज्य का करीब 10,459 करोड़ रुपये लंबित है। मैंने इस मामले से प्रधानमंत्री को अवगत कराया है और उन्होंने शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ममता ने कहा कि पीएम ने कहा कि इस मामले में जल्द ही कुछ करेंगे। मोदी और ममता की आज की मुलाकात उनके राजनीतिक रिशतों पर जमी बर्फ को एक हद तक पिघलाने का काम करेंगी। वहीं ममता व मोदी की मुलाकात के राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष व सांसद अधीर चौधरी का कहना है कि दरअसल ममता राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा करने नहीं गई थीं। उन्होंने नारद व सारथा घोटाले में फंसे अपने नेताओं को बचाने के लिए पीएम के साथ एकांत बैठक की है। यदि आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होनी थी तो फिर वित्तमंत्री व वित्त विभाग के अधिकारियों को वहां मौजूद होना चाहिए था। वहीं माकपा के वरिष्ठ नेता व सांसद मोहम्मद सलीम का कहना है कि यह सिर्फ सियासी बैठक थी जहां मुख्यमंत्री राजनीतिक मोलभाव के लिए ही आई थीं।

न्यायपालिका में महिलाएं

मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई - भारत के इन चार महानगरों को कौन नहीं जानता। मेट्रो शहर होने के अलावा ये हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी की भी हैं, लेकिन अब इन चारों महानगरों ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। इन महानगरों के ऐतिहासिक हाईकोर्ट में महिलाएं चीफ जस्टिस के पद पर विराजमान हुई हैं। देश के इतिहास में पहली बार यह मौका आया है जब औपनिवेशिक भारत में बने इन चार उच्च न्यायालयों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। देश के उच्च न्यायालयों में महिलाओं के वर्चस्व की शुरुआत अप्रैल 2014 से हुई जब दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति जी रोहिणी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। इसके बाद पिछले साल 22 अगस्त को जस्टिस मंजुला चेल्लूर बांब्वे हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीशा बनीं। फिर वर्ष दिसंबर में निशिता निर्मल हव्नेर कलकत्ता हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशा बनीं और इस साल 31 मार्च को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इंदिरा बनर्जी की नियुक्ति की गई।

हालांकि इन उच्च न्यायालयों में महिला चीफ जस्टिस की नियुक्ति होना एक उपलब्धि है, लेकिन इस खुशी के बावजूद हमारी न्यायपालिका में महिलाओं की संख्या का एक स्टाइ होनी चाहिए।

फिर से

देश के चार प्रमुख हाईकोर्ट में महिलाएं चीफ जस्टिस के पद पर काबिज हुई हैं, लेकिन न्यायपालिका में उनकी भागीदारी अभी भी कम है

है। हमारे न्यायालयों में महिलाओं की संख्या को अगर देखें तो स्पष्ट होता है कि कुल मिलाकर यह क्षेत्र हमारे यहां अभी भी पुरुषों के वर्चस्व वाला ही है। आप मानें या न मानें हमारे देश के 24 उच्च न्यायालयों में 632 न्यायाधीश हैं। इनमें से सिर्फ 10.7 प्रतिशत यानी 68 महिलाएं हैं।

एक नजर इन उच्च न्यायालयों में महिला जजों की संख्या पर डालें तो और भी कड़वी सच्चाई सामने आ जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय में हर 35 पुरुष जजों की तुलना में केवल नौ महिला जज हैं। दूसरी तरफ मद्रास हाईकोर्ट में तो स्थिति और भी खराब है। यहां हर 53 पुरुष जजों पर सिर्फ छह महिला जज हैं। बांब्वे हाईकोर्ट में 61

पुरुष न्यायाधीशों पर 11 महिला न्यायाधीशों की संख्या फिर भी बाकियों की तुलना में थोड़ी बेहतर है। हालांकि सबसे बुरा हाल कलकत्ता हाईकोर्ट का है। यहां पुरुष-महिला जजों की संख्या का अनुपात तो 35 में सिर्फ चार का है।

अगर सुप्रीम कोर्ट में महिला जस्टिस की संख्या देखें तो 28 जजों में सिर्फ एक महिला जज और बानुमथी हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इतिहास को देखें तो और भी बेहतरअंगेज तत्करीर उपर कर सामने आती है। 1950 से आजतक देश के सर्वोच्च न्यायालयों में सिर्फ छह महिला जजों की नियुक्ति हुई है। सुप्रीम कोर्ट में किसी महिला जज की नियुक्ति होने में 39 साल लग गए थे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली पहली महिला जज केरल हाईकोर्ट की फातिमा बीबी थीं। इन संख्याओं को देखकर निराशा तो होती है, लेकिन कहते हैं न कि उम्मीद की राहें अनंत हैं। हमें भी उम्मीद का दामन थामे रहना चाहिए। बदलाव की लौ जलने लगी है बस अब इसे बुझने नहीं देना है। इसके लिए सभी स्तरों पर प्रयास करने होंगे और इस मुहिम की कमान भी महिलाओं को ही थामनी होगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हित उनका ही निहित है।

(साभार : आइचौकडॉटइन में रिम्मी कुमारी)



डॉ. भरत झुनझुनवाला

अभी सरकार पर दबाव है कि उत्पादन बढ़ाकर किसानों का भला करे, लेकिन असल में उत्पादन घटाकर ही किसानों के हित साधे जा सकते हैं

आठ साल पहले केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का कर्ज माफ किया था। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी की है। दस वर्षों से भी कम अंतराल में किसानों का कर्ज दोबारा माफ करना पड़ा है। यह दर्शाता है कि मौजूदा व्यवस्था में किसान कर्ज लेते रहेंगे और सरकारें उसे माफ करती रहेंगी। कर्ज माफी किसान की समस्या का निदान नहीं है। यह कुछ बैसा है मानो कैसर के मरीज को सिरदर्द की गोली दी जा रही हो। किसान इसलिए कर्ज अदा नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आमदनी कम है। दूसरी ओर सरकार की आर्थिक समीक्षा के अनुसार किसान की आय बढ़ रही है। समीक्षा के अनुसार 2005 से 2014 के दौरान सभी वस्तुओं के मूल्य का सूचकांक 100 से बढ़कर 180 हो गया। इस दौरान खाद्यान्नों के मूल्य का सूचकांक 100 से चढ़कर 231 हो गया। यानी सभी वस्तुओं की तुलना में खाद्यान्न की कीमतों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है। किसान की लागत जरूरी बढ़ी है, लेकिन उसके बनिबत्त आमदनी में ज्यादा इजाफा हुआ है। ऐसे में यह विडंबना ही है कि आय बढ़ने के बावजूद किसान कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। हैरानी की बात है कि किसान पर कर्ज खेती के कारण नहीं बढ़ रहा है। जानकारों के अनुसार किसान बेटी के विवाह, भ्रमण, वाहन और अन्य कई निजी जरूरतों पर कर्ज की राशि खर्च करते हैं। चूंकि आमतीर पर बैंक उन्हें इन जरूरतों के लिए कर्ज

नहीं देते तो वे बीज, खाद या फसली कर्ज के नाम पर कर्ज लेकर इन जरूरतों को पूरा करते हैं। आय की तुलना में किसान की जरूरतें ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। पहले किसान पैदल चलता था। आय बढ़ी तो साइकिल खरीदने में सक्षम हो गया, मगर उसकी जरूरत बाइक खरीदने की हो गई है। इसकी पूर्ति वह कर्ज से करता है। आमदनी के अभाव में कर्ज अदा हो नहीं पाता। साइकिल की हैसियत में बाइक की सवारी उस पर भारी पड़ती है। किसान का कोई दोष नहीं है। वह भी शहरों जैसी आधुनिक जीवनशैली के मोहपाश में फंसा है। शहरी लोग बाइक चलाएं और किसान की बेटी साइकिल से स्कूल जाए, यह उसे गबाय नहीं। होना भी नहीं चाहिए। गांव और शहर के बीच बढ़ती खाई भी किसान पर बढ़ते कर्ज का एक पहलू है।

कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा के अनुसार 1970 से 2015 के बीच कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में 20 गुने का इजाफा हुआ है। इसके मुकाबले सरकारी कर्मियों के वेतन में 120 गुना वृद्धि हुई है। आय का यह असंतुलन किसान के कर्ज का कारण है। सरकार की सोच है कि उत्पादन बढ़ाने से किसान की आय बढ़ाई जा सकती है। सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा, कर्ज पर सब्सिडी, ड्रिप सिंचाई, सड़कें और कोल्ड स्टोरेज जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बीते 70 सालों से यह सिलसिला जारी है, फिर भी उत्पादन बढ़ने से किसान की आमदनी में अपेक्षित वृद्धि का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। ऐसे में मौजूदा सूरतहाल में भी उत्पादन बढ़ाने से आय



अवधेश राजू

में वांछित वृद्धि नहीं हो पाएगी। बड़े उत्पादन के साथ और भी समस्याएं जुड़ी हैं। मसलन उसकी खपत कहां हो? देश में उनका उपभोग सीमित है। अक्सर सुनने को मिलता है कि बंपर फसल होने के कारण भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में भी भंडारण के लिए जगह कम पड़ जाती है और अनाज खुले में सड़ने पर मजबूर होता है। निर्यात से भी इसका हल नहीं हो सकता। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक 2011 में खाद्य पदार्थों के मूल्य का वैश्विक सूचकांक 229 था जो 2016 में घटकर 151 रह गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्यान्न के दाम गिर रहे हैं। इन गिरते मूल्यों के कारण खाद्यान्न का निर्यात करने के लिए सरकार को निर्यात सब्सिडी देनी होगी, लेकिन डब्ल्यूटीओ के नियमों में निर्यात सब्सिडी पर प्रतिबंध है। ऐसे में बड़े उत्पादन को अंततः घरेलू बाजार में ही बेचना होगा। इससे दाम गिरेंगे। बढ़ता उत्पादन हमारे किसानों के लिए ही अभिशाप बन गया है जैसा कि बीते दिनों किसानों

को मजबूरन आलू सड़कों पर फेंकना पड़ा था। कुल मिलाकर उत्पादन बढ़ाकर किसान की आय नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि बड़े उत्पादन को खपाने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। जैसे बाढ़ का पानी नहीं निकल पाने के कारण लोग डूबते हैं उसी तरह कृषि उत्पादन का निस्तारण न होने की वजह से किसान कर्ज में डूब रहे हैं। इस समस्या का हल कृषि के दायरे में उपलब्ध है ही नहीं। केवल खेती से किसान की आय नहीं बढ़ाई जा सकती है। इस समस्या का एक समाधान यह हो सकता है कि किसान को भूमि के आधार पर सब्सिडी दी जाए। अमेरिका में किसानों को भूमि परती छोड़ने के एवज में सब्सिडी दी जाती है। इससे उन्हें ठीक-ठाक आमदनी हो जाती है। ऐसे में शेष उत्पादन को औने-पौने दाम पर बेच कर भी वे बाइक खरीद पाते हैं। इस पद्धति को हम भी अपना सकते हैं। देश में लगभग दस करोड़ किसान हैं जिनमें सात करोड़ से पास एक एकड़ से कम भूमि है। प्रारंभ

संवादहीनता से जूझती कांग्रेस

अपने सबसे मुश्किल वक्त से जूझ रही कांग्रेस को गहन आत्मचिंतन की जरूरत है

लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी हार-जीत कोई नई बात नहीं। राजनीतिक दलों के इतिहास में कभी जीत की दिमांस तो कभी हार की मायूसी के क्षण आते ही रहते हैं। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के रूप में जो तत्कालीन सामने आई वह देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए मायूसी से कहीं आगे बेहद स्तब्ध करने वाली रही। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों के बाद पार्टी जिस मोड़ पर खड़ी है वह मामूली राजनीतिक परिस्थिति नहीं। इसकी गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं बहुलतावादी संवैधानिक लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले भी कांग्रेस के इस हालत में पहुंचने को लेकर चिंता जता रहे हैं। यह चिंता अस्वाभाविक नहीं, क्योंकि बहुलवादी लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हुए इस मुकाम तक लाने में कांग्रेस की महती भूमिका रही है। छह दशक तक देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस की यह पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वह बेबाकी से आत्मचिंतन करें कि वह इस मुकाम पर क्यों और कैसे पहुंच गई कि आज उसके अस्तित्व को लेकर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस की मौजूदा हालत को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि शुरुआत संग्रम के केंद्र की सत्ता में दोबारा वापसी के एक साल बाद ही शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश के 2012 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्यप्रदेश और दिल्ली के चुनावों में पार्टी की शिकस्त के बाद भी कांग्रेस की रीति-नीति चलाने वालों की शैली और सोच में बदलाव नहीं आया। 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार विपक्ष की हैसियत लाकफ सीटें हासिल नहीं कर पाने की बेहद कड़वी सच्चाई सबके सामने थी, फिर भी पार्टी इस कठिन परिस्थिति से बाहर आने का कोई रास्ता तलाश नहीं कर पाई।

उत्तर प्रदेश के नतीजों ने कांग्रेस को झकझोर कर रख दिया है। पंजाब की जीत और मणिपुर-गोवा में संतोषजनक प्रदर्शन को चांदर से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की मौजूदा चुनौती को ढंकना पार्टी के समक्ष मौजूद सबसे विकराल चुनौती से मुंह मोड़ना होगा। यह तर्क सही हो सकता है कि उत्तर प्रदेश को सत्ता की सियासत में कांग्रेस मुख्य नहीं बल्कि सहાયक खिलाड़ी थी, पर इस तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 22 सीटें मिली थीं और वह सपा के बाद दूसरे नंबर की पार्टी थी। तब 10 लोकसभा सीटों के साथ भाजपा चौथे नंबर पर थी और आज हालात यह है कि कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर बहस हो रही है। कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर शुरू इस बहस में राजनीतिक विश्लेषकों के जल्दबाजी भरे निष्कर्ष



अशुमान राव



कांग्रेस कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं कि केवल जनता ही नहीं, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं से भी कट गई है

से बेशक न पार्टी सहमत है और न ही कार्यकर्ता, क्योंकि कांग्रेस की राजनीतिक चिंतनधारा देश की व्यापक जनता के मन मस्तिष्क में है। केवल चुनावी हार से सर्वसमावेशी लोकतंत्र में भरोसे की यह सोच खत्म नहीं होगी, लेकिन जनता का यह भरोसा न टूटे, यह सुनिश्चित करना भी पार्टी के लिए चुनौती है। इसके लिए अपनी अंदरूनी खामियों का बेबाकी से आत्मविश्लेषण अपरिहार्य है। अब उन सवालों को नजरअंदाज करने का वक़्त नहीं है जो बाहर और अंदर, पूछे जा रहे हैं।

पिछले बीस-तीस सालों से कांग्रेस में संगठन और सियासत को संचालित करने वालों को इस सवाल का जवाब तो देना ही चाहिए कि आखिर इस कालखंड में राज्यों से लेकर केंद्रीय स्तर पर पार्टी में नए जमीनी नेताओं की फौज क्यों नहीं तैयार हो पाई? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में नए ताकतवर क्षेत्रीय केंद्र क्यों नहीं उभर कर सामने आए? इतिहास गवाह है कि देश में कांग्रेस की ताकत हमेशा उस समय सबसे ज्यादा रही जब सुबों में उसके क्षेत्रप मजबूत सियासी चेहरे रहे। कांग्रेस के शिखर नेतृत्व को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में न पहले संशय

था और न अब है, मगर पार्टी का संचालन करने वालों को यह बताना चाहिए कि एक दशक से बदलाव की शिखर नेतृत्व की ओर से उठ रही आवाज पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? यह स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि बीते दो दशक में राजनीति ही नहीं लोगों का मिजाज और अपेक्षाएं भी बदली हैं। सामाजिक और आर्थिक बदलाव के मौजूदा परिवेश में कांग्रेस को भी नई चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए 2006 में सोनिया गांधी ने एक कमेटी बनाकर आगे बढ़ने का रोडमैप बनाने का जिम्मा सौंपा था। पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं पता कि इस रोडमैप का क्या हुआ और उसमें क्या है? इसी तरह पिछले लोकसभा चुनाव के बाद एके एंटनी की अगुआई में पराजय के कारणों का विश्लेषण करने के लिए एक कमेटी बनी थी। यदि इस कमेटी की रिपोर्ट पर अमल किया गया होता तो शायद पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे स्तब्धकारी हालात का सामना करने में अधिक सक्षम होती। पार्टी की रीति-नीति का संचालन करने वाले भले ही इस बात को तबज्जो न दें मगर पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता शिदत से यह महसूस कर रहे हैं कि जनता ही नहीं पार्टी कैडर से भी संवादहीनता की स्थिति पिछले कई सालों में कायम है। शायद इसीलिए जनता के नजरिये से संवेदनशील मुद्दों पर जब-जब अलग लाइन ली गई तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। ऐसी स्थिति इसलिए बनी, क्योंकि पार्टी के संचालकों की टीम वही है जो दो दशक पहले भी थी। इसमें कुछ चेहरे तो बड़े हो सकते हैं, मगर अब उनका राजनीतिक जमीन वेंसी नहीं रही कि संवाद की पुरानी ताकतवर परंपरा को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने पार्टी कैडर ही नहीं जनता से दोतरफा सीधे संवाद के सहारे भरोसा पैदा करने की चुनौती है। कांग्रेस आज संक्रमण के जिस दौर में है वहां महज शब्दों से भरोसा पैदा करना कठिन काम है। इसके लिए आवश्यक है कि पार्टी उन खामियों को दूर करने की दिशा में तत्काल कदम उठाए जिसे लेकर पार्टी के भीतर से भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में यह वाद रखना होगा कि किसी भी पहलू की मद्दत चुनाव और सत्ता की राजनीति से जोड़ कर ही न देखा जाए। नई पीढ़ी को जोड़ना और कांग्रेस को लेकर उनमें राजनीतिक रोमांच की भावना जागृत करना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। कमजोरियों को विना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करने हुए सुधारात्मक पथ पर आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो वांछित परिणाम अर्जित करना नामुमकिन नहीं।

(लेखक कांग्रेस के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं)

response@jagran.com

मेलबाक्स

लोगों पर दाव लगाना चाहती है। दिल्ली और केंद्र की आपसी तनतानी से दिल्ली कूड़े ढेर लगने के कारण कितने दिनों नरक बनती रही जिसे जनता भूली नहीं है। ऐसी स्थिति में तो कांग्रेस को भी लाभ हो सकता है। यूपी में योगी सरकार बड़ी तेजी से कार्य करने में लगी है इसका प्रभाव भी दिल्ली पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर इस चुनाव में किसी की विरोधी लहर नहीं है। अब देखना यह है कि जनता किस को ताज़ सौंपेगी।

vednamurpur@gmail.com

मान-सम्मान मिले

हमारे देश में गौ माता को पूजनीय माना जाता है। लंबे समय से राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग भी चल रही है। यह अच्छी बात है, गाय से होने वाले फायदे को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना भी चाहिए। अभी हाल ही में हुई अलवर की घटना में गांव व व्यक्ति का नाम सुनकर ही पीट-पीट कर मार डाला। तो भाई यह बताओ कितनी माताएं चाहती हैं कि उनकी वजह से उनके बच्चे मारे जाएं। यह तो गौ माता के नाम से केवल समाज में समुदाय की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो घटना अभी राजस्थान में हुई है वह पहले भी कई राज्यों में हो चुकी है। इस तरह अफवाह फैलाकर निर्दोष लोगों के साथ भारपीट जैसी घटनाओं को रोकना होगा। इसके लिए प्रशासन को उचित कदम उठाने होंगे। हम भी आपकी तरह इस बात से सहमत हैं कि गोकशी पर पर रोक लगे, गाय को उचित मान-सम्मान मिले, लेकिन इस तरह निर्दोष लोगों की जान लेकर व उन पर अत्याचार करने नहीं।

vijaykumardhania@gmail.com

मे इन्हे 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की सब्सिडी दी जा सकती है। सरकार को इस पर 42,000 करोड़ रुपये सालाना खर्च करने होंगे जो वर्तमान में मनरेगा पर किए जा रहे खर्च के बराबर है। इस सब्सिडी से किसानों को सीधे राहत मिलेगी। वह किस्त पर बाइक खरीद सकेगा। इसमें खास बात यही है कि उसके उत्पादन कम करने से बाजार में कृषि उत्पादों के दाम बढ़ेंगे और परिणामस्वरूप किसान की आय बढ़ेगी। इसके उलट हमने यही देखा कि उत्पादन बढ़ने से दाम घटते हैं और किसान की आय कम होती है। वहीं उत्पादन कम होने से बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति कम होती है तो दाम बढ़ते हैं जिससे किसानों की आय बढ़ सकती है। आय बढ़ाने के लिए उत्पादन का एक विशेष स्तर कारगर होता है जैसे स्वास्थ्य सुधार के लिए घी की एक निश्चित मात्रा उपयुक्त होती है। इस विशेष स्तर से अधिक उत्पादन और इस स्तर से कम उत्पादन दोनों ही किसान के लिए नुकसानदेह होते हैं। फिलहाल तो सरकार पर दबाव यही है कि उत्पादन बढ़ाकर ही किसानों का कल्याण किया जाए, लेकिन असल में उत्पादन घटाकर ही किसानों के हित साधे जा सकते हैं।

कृषि क्षेत्र में हमारी नीति में मौलिक बदलाव की जरूरत है। किसान की इच्छा है कि वह भी सरकारी-निजी नोकरीशा लोगों की तरह बाइक पर घुमे। इस हसरत में कोई बुराई नहीं, लेकिन इसके लिए उसकी आय में वृद्धि जरूरी है, मगर उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहन देकर हम किसान को समाधान के बजाय संकट की ओर ही धकेल रहे हैं। वक़्त का तकाजा तो यही कहता है कि किसानों को भूमि पर सीधे सब्सिडी दी जाए।

(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं अइआइएम

बंगलुरु के पूर्व प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com



परमात्मा की शक्ति

जब मनुष्य की सभी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और वह स्वयं को लाचार महसूस करता है तब उसे परमात्मा की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रत्येक क्षण परमात्मा की शक्ति पर विश्वास बनाए रखते हैं वह कभी परेशान-हेरान नहीं रहते, बल्कि ऐसे व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में करने की क्षमता रखते हैं। परमात्मा की शक्ति असीम होती है और इसके बल पर मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की शक्ति से हम कर सकते हैं। जब मनुष्य के मन में परमात्मा के प्रति भक्ति भाव जाग्रत होता है तो उसे कुछ भी अपने विपरीत लगना ही नहीं। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति का आनंद लेते हैं और यह मानते हैं कि इतिहास परिस्थितियों की उनके अनुकूल ही हैं। ऐसे में मनुष्य को लगता है कि प्रत्येक कार्य परमात्मा की इच्छा से ही हुआ है, इसलिए विपरीत परिस्थितियां भी जरूर उनके हित में होंगी। ऐसे व्यक्ति अपना सर्वस्व परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं और उनके जीवन में बुरा समय भी आता है तो वे उसका मुकाबला धैर्य और साहस से करते हैं। गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरी शरण में आता है वह भवसागर पर कर लेता है। मनुष्य को हमेशा यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसके विकास का आधार आलस्य नहीं, बल्कि विषम परिस्थितियां हैं। इसलिए उसे विपरीत समय में संताप करने के बजाय डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। मनुष्य अपने धैर्य, साहस और बुद्धि के पराक्रम से किसी भी तरह की परिस्थिति का सामना कर सकता है। जो व्यक्ति स्वयं अपनी मदद करते हैं उन्हें ही परमात्मा की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन के हर मोड़ पर सीखने का भाव और कठिन परिस्थिति को आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में परमात्मा की शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए उसे हमेशा परमात्मा को याद करते रहना चाहिए। फिर चाहे वह सुखमय जीवन जी रहा हो या फिर दुख में हो। दुख में हर कोई परमात्मा की याद करता है, लेकिन सुख में नहीं। यदि मनुष्य सुख में भी परमात्मा को याद करे तो उसे दुख आएगा ही नहीं। जीवन में आस्था, सम्पण और त्याग के भाव ही हमें परमात्मा से जोड़ते हैं।

महायोगी पायलट बावा

बदलाव की उम्मीद

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वसूल जाने वाले समस्त अप्रत्यक्ष कर अब जीएसटी में समाहित हो जाएंगे। इससे व्यवसायियों, बड़े-बड़े उद्योगपतियों के साथ ही आम जनता को भी फायदा होगा। उद्योगपतियों को जहां कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर की जगह अब एक ही कर चुकाना होगा। वहीं आम जनता को पहले की तुलना में अब वस्तुएं एवं सेवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी। जीएसटी के लागू होने पर कर चोरी पर अंकुश लगेगा जिससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। जिससे सरकार को जनकल्याण पर खर्च करने के लिए अधिक धनराशि मिल सकेगी। जीएसटी का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह 'सहयोगात्मक संघवाद' का सर्वोत्तम प्रारूप है। जीएसटी परिपद में कोई भी नियम 75 फीसद के बहुमत से लिया जाएगा। जिसमें फंडास 33 फीसद मताधिकार केंद्र सरकार के पास एवं 42 फीसद मताधिकार राज्यों के पास है।

subhashkumarthakur2(w@gmail.com

इस संक्षेप में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा ई-मेल : mailbox@jagran.com

 सेंसेक्स	29575.74	 निफ्टी	9181.45	 सोना	₹29290	 चांदी	₹ 41800	 डॉलर	₹ 64.57	 यूरो	₹68.26	 पाउंड	₹80.04	 येन	₹ 58.01	 क्रूड (बैट)	\$ 55.89
	▲ -130.87		▼ -16.85		▼ ₹ 10		▲ ₹ 50		▲ ₹ 0.28		▼ ₹ 0.09		▲ ₹ 0.21		▼ ₹ 0.08		प्रति बैरेल

कार्पोरेट हलचल

ओएनजीसी एवरैस्ट एक्सपीडिशन 2017

ओएनजीसी के 11 सदस्यीय एवरैस्ट पर्वतारोहण दल ने काठमांडू से अपना अभियान शुरू किया। यह पहला मौका है जब किसी कॉर्पोरेट घराने का अपना पर्वतारोही दल माउंट एवरैस्ट अभियान पर गया है। ओएनजीसी ने यह अभियान दल अपने युवाकर्मियों को पर्वतारोहण के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से भेजा है।

एनएफएल का रिकॉर्ड उत्पादन

नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एनएफएल) ने साल 2016-17 के दौरान 118 फ़ैसद की कुल क्षमता उपयोग के साथ 38.10 लाख टन यूरिया का उत्पादन किया है। यह यूरिया उत्पादन के मामले में कंपनी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। साल 2015-16 में 37.99 लाख टन का उत्पादन किया गया था। कंपनी ने नाइट्रिक एसिड और अमोनियम नाइट्रेट सहित औद्योगिक उत्पादों के रिकॉर्ड उत्पादन व 189 करोड़ रुपये की बिक्री का रिकॉर्ड स्थापित किया।

सीएसआइआर की गवर्निंग बॉडी में ओएनजीसी सीएमडी

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओएनजीसी के सीएमडी दिनेश सराफ को परिषद की कार्यकारी समिति में मनोनीत किया है। सराफ का मनोनयन तीन साल की अवधि के लिए हुआ है। सीआइएसआर की गवर्निंग बॉडी शि परिषद के सभी चारमंडलन के लिए उत्तरदायी होती है।

एनटीपीसी बदरपुर का सीएसआर

एनटीपीसी बदरपुर ने आइटीआइ मालवीय नगर के मेवाबी छात्रों को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 37 छात्रों, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग ट्रेड के 23 छात्रों को टूल किट प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में बदरपुर स्टेशन के समूह महाप्रबंधक नीरज कुमार सिंह का मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

आइसीएआर का स्थापना दिवस

चेन्नई स्थित आइसीएआर ने 4 अप्रैल को अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। इस दिवस को स्कूली छात्रों के लिए ओपन डे की हैसियत से मनाया गया। स्कूली छात्रों को इस दिन आइसीएआर की प्रयोगशालाओं को अवलोकन करने का मौका मिला। संस्थान ने ऐसा स्कूली छात्रों में कृषि और अन्य सहायोगी क्षेत्रों में अनुसंधान के प्रति रुचि जागृत करने के उद्देश्य से किया था।

रेलवे की सप्लाई चेन का डिजिटाइजेशन

नई दिल्ली, प्रे्ट : भारतीय रेलवे अपने सभी रेलवे जोनों में समूची सप्लाई चेन का डिजिटाइजेशन करने जा रही है। इसके साथ ही रेलवे डिजिटल कांट्रेन्ट लांच कर देगा। रेलवे ने कारोबारी सुगमता और पारदर्शिता में सुधार लाने के मकसद से यह कदम उठाया है। इससे रेलवे की लागत में भी कमी आयेगी। खरीद का समय बचेगा और खरीद में फिकायत होगी। भारतीय रेलवे हर साल करीब 50 हजार करोड़ रुपये का व्यय करके तमाम तरह की खरीद करती है।

रेलवे अपने सिस्टम में ई-टेंडरिंग और ई-ऑक्शन को पूरी तरह लागू कर चुका है। सप्लाई चेन का डिजिटाइजेशन होने से उसके मैटीरियल, फाइनेंस और सुचनाओं का आबाध आवागमन सुनिश्चित हो सकेगा। इससे रेलवे की कार्यकुशलता और उत्पादकता में सुधार होने की संभावना है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु 11 अप्रैल को डिजिटल कांट्रेन्ट को लांच करेंगे। डिजिटल कांट्रेन्ट समग्र डिजिटल सप्लाई चेन है। इस सप्लाई चेन से सभी पक्ष जैसे उद्योग, वित्तीय संस्थान, रेलवे के आंतरिक कस्टमर और निरीक्षण एजेंसियां जुड़ेंगी। इससे समूची चैन ज्यादा कार्यकुशल, जवाबदेह और पारदर्शी हो जाएगी।

नये ऐसेट विकसित करता है। इसके बल पर ही वह सुरक्षित और कार्यकुशल सेवाएं प्रदान करती है। उसके सिस्टम से बड़ी संख्या में कंपनियां और सप्लायर जुड़े हैं। इस पर रेलवे हर साल करीब 50 हजार करोड़ रुपये खर्च करता है। उसकी सप्लाई चेन से बड़े पैमाने पर कारोबार होता है और लाखों की संख्या में रोजगार पैदा होते हैं। इस लिहाज से यह रेलवे के लिए अत्यंत अहम काम है।

अधिकारी के अनुसार प्रक्रिया के डिजिटाइजेशन से रेलवे अपने बजट को परिणामों को सीधे तौर पर जोड़ सकेगा। सरकार इस पर खासा जोर दे रही है। रेलवे पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुधारने के लिए इन्फोमेशन व कम्प्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। इस कदम से फैसेल लेने के लिए एनालिटिक्स का इस्तेमाल संभव होगा। रेलवे इसके चलते अपनी इन्वेन्टी घटा सकेगी और खरीद का समय भी कम कर सकती है। इससे रेलवे की लागत में भी कमी आएगी। इससे कारोबारी सुगमता को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार इस पर लगातार जोर दे रही है।

तैयारी ▶ नागपुर में अंबेडकर जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में होगी घोषणा

पीएम करेंगे आधार भुगतान का एलान

डिजिधन स्कीम के विजेता को

इसी कार्यक्रम में दिया जाएगा

पुरस्कार

नितिन प्रधान, नई दिल्ली

सरकार अंबेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल को आधार के जरिये भुगतान की व्यवस्था शुरू करने का एलान कर सकती है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित कार्यक्रम से इसकी शुरुआत हो सकती है। डिजिधन योजना के तहत घोषित एक करोड़ रुपये के पुरस्कार के विजेता को इसी कार्यक्रम में पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

सरकार ने अंबेडकर जयंती के मौके पर नागपुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ इस कार्यक्रम

में हिस्सा लेंगे। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री इसी कार्यक्रम में बहुप्रतीक्षित आधार आधारित भुगतान व्यवस्था के लांच की घोषणा करेंगे। इसी दिन इस सिस्टम को मौजूदा भीम एप से जोड़ने की घोषणा भी हो सकती है। कार्यक्रम में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, ऊर्जा कोयला खान व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री पीठूप गोंगल, मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फगनवीस समेत कुछ राज्य मंत्री भी हिस्सा लेंगे।

आधार आधारित भुगतान व्यवस्था के शुरू होने के बाद लोग केवल अपने अंगुठी की पहचान के आधार पर भुगतान कर सकेंगे। फिलहाल देश में आधार धारकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हो गई है। जिन लोगों के बैंक खाते आधार के साथ लिंक हो गए हैं, वे सभी इस व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। वैसे सरकार ने सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ने की मुहिम शुरू की है। अब तक 42 करोड़



देश में आधार धारकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक है। अब तक 42 करोड़ बैंक खाते भी आधार से जुड़े

खाते आधार से लिंक किये जा चुके हैं। 18 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र वाले लगभग प्रत्येक व्यक्ति को आधार मिल चुका है।

जल्द ही मोबाइल के जरिये निकाल सकेंगे ईपीएफ

नई दिल्ली, प्रे्ट : जल्द ही कर्मचारी मोबाइल एप 'उमंग' के जरिये अपना ईपीएफ निकाल सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) इस एप के जरिये पीएफ दावे निपटाने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने लोकसभा में यह जानकारी दी। इससे कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अंशदान करने वाले साढ़े चार करोड़ लोगों को फायदा होगा।

दत्तात्रेय ने कहा कि ईपीएफओ पीएफ दावे (क्लेम) के आवेदन ऑनलाइन तौर पर प्राप्त करने के लिए तैयारी में लगा है। संगठन इसके तहत ऑनलाइन दावा निपटान प्रक्रिया विकसित कर रहा है। ऑनलाइन क्लेम प्राप्त करने के लिए आवेदन को यूनीफाइड मोबाइल एप फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) से जोड़ा जाएगा। हालांकि मोबाइल एप के जरिये दावों का निपटान शुरू करने की कोई समय तय नहीं की गई है।

पीएफ निकासी, पेंशन निर्धारण या ग्रुप इंश्योरेंस बेनिफिट सेटलमेंट के लिए ईपीएफओ के पास सालाना एक करोड़ आवेदन किए जाते हैं। फिलहाल इन दावों का निपटारा मैनुअल ढंग से किया जाता है। ईपीएफओ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 123 फील्ड

ऑफिस में से 110 कार्यालयों को पहले से सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट किया जा चुका है। ऑनलाइन दावा निपटान की सुविधा शुरू करने से पहले सभी फील्ड ऑफिस का केंद्रीय सर्वर से जुड़ना जरूरी है। इसके अलावा पीएफ क्लेम ऑनलाइन निपटाने के लिए भविष्य निधि संबंधी यूनिवर्सल एकाउंट नंबर के साथ आधार नंबर और बैंक खाते का जोड़ना आवश्यक है।

श्रम मंत्री ने बताया कि ईपीएफओ ने टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक), पुणे को तकनीकी सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है। ईपीएफओ अपने तीन केंद्रीय डाटा केंद्रों- दिल्ली, गुरुग्राम और सिकंदराबाद को आधुनिक उपकरणों से लैस कर रहा है।

तीन घंटे में दावे निपटाने का लक्ष्य : इससे पहले केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने जानकारी दी कि ईपीएफओ मई से ऑनलाइन क्लेम सेटल करने की सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। संगठन का लक्ष्य सदस्यों के ऑनलाइन आवेदन करने के बाद तीन घंटे के भीतर पीएफ संबंधी दावों का निपटारा सुनिश्चित करने का है।

सतर्कतावश दलाल स्ट्रीट में बिकवाली

मुंबई, प्रे्ट : आर्थिक आंकड़े और कंपनी नतीजे आने से पूर्व निवेशकों ने सोमवार को सतर्कता भरी बिकवाली की। इसके चलते दलाल स्ट्रीट में सोमवार को लगातार तीसरे सत्र में गिरावट जारी रही। इस दिन बंबई शेयर बाजार (बीएसई) का सेंसेक्स 130.87 अंक फिसलकर करीब दो हफ्ते के निचले स्तर 29575.74 पर बंद हुआ। इन तीन सत्रों के दौरान यह संवेदी सूचकांक 398.50 अंक नीचे आ चुका है। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 16.85 अंक टूटकर 9181.45 पर बंद हुआ।

फक्वरी के औद्योगिक उत्पादन और मार्च की खुदरा महंगाई के आंकड़े बुधवार को आएंगे। ताजा बिकवाली के लिए बड़ी बात फोरी ट्रिगर बनी। इसके अलावा नुस्खे से कंपनियों के वित्तीय नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। इस दिन प्रमुख आइटी कंपनी इफोसिस अपने परिणामों का एलान करेगी। इसके अलावा अमेरिका की ओर से सीरिया पर वीते हफ्ते हुए मिसाइल हमले के चलते भू-राजनीतिक तनाव बना हुआ है। इन सब वजहों से निवेशक सतर्क रख अपनाते हुए बिकवाली कर रहे हैं।

बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 29752.62 अंक पर मजबूत खुला। ऊंचे में यह 29831.22 अंक तक गया। बाद में बिकवाली के दबाव में कारोबार के दौरान एक समय यह सत्र के निचले स्तर 29553.04 अंक को छू गया। इस दिन आइट्टी, टेक्नोलॉजी, रियल्टी, कंप्यूटर हार्डवेयर और पावर कंपनियों के शेयरों पर बिकवाली की मार पड़ी। सेंसेक्स की तीस कंपनियों में 16 के शेयर नुकसान में रहे, जबकि 14 में फायदा दर्ज हुआ।

रुपया 28 पैसे कमजोर

मुंबई : डॉलर के मुकाबले तीन सत्रों तक लगातार मजबूत होने के बाद रुपये ने अब नीचे का रुख पकड़ लिया। भू-राजनीतिक के चलते सोमवार को अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के सामने रुपये में तीन माह की सबसे बड़ी 28 पैसे की गिरावट दर्ज हुई। इस दिन भारतीय मुद्रा 64.57 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई।

प्रतिद्वंद्विता

शिकायत में कहा गया है कि कथित तौर पर जियो ग्राहकों को एसएमएस भेजकर स्क्रीम का लाभ लेने के लिए तुरंत रिचार्ज करने को प्रोत्साहित कर रही है।



नई दिल्ली, प्रे्ट : टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन ने ट्राई से शिकायत की है कि रिलायंस जियो अभी भी ग्राहकों को समर सप्राइज ऑफर के जरिये लुभा रहा है जबकि वह जियो के इस ऑफर को नियमों के विरुद्ध बता चुका है।

वोडाफोन ने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्रि के भेजे पत्र में कहा है कि रिलायंस जियो ग्राहकों को लगातार समर ऑफर दे रही है। जबकि यह ऑफर ट्राई के मानकों को पूरा नहीं करता है। वोडाफोन ने कहा कि पिछले तीन दिनों से जियो मानकों के विरुद्ध इस ऑफर का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को तुरंत रिचार्ज करने के लिए लुभा रही है और इसे बढ़ावा दे रही है। शिकायत पत्र में कथित तौर पर रिलायंस जियो द्वारा ग्राहकों और रिटेलर्स को भेजे गये एसएमएस का भी हवाला दिया गया है, जिसमें स्क्रीम का लाभ लेने के लिए तुरंत रिचार्ज करने को कहा गया है। एसएमएस में लिखा है कि जियो ने ग्राहकों को स्क्रीम में शामिल होने के लिए 10 अप्रैल तक का समय दिया है।

प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने 31 मार्च को घोषणा की थी कि अभी तक प्रारंभ मेंबरशिप प्लान में पंजीकरण नहीं करने वाले ग्राहकों को 15 अप्रैल तक 99 रुपये जमा कवाकफर प्लान लेना होगा

कतर एयरवेज की सहयोगी बेंगलुरु में बनाएगी बेस

मुंबई : कतर एयरवेज की भारतीय सब्सिडियरी अपना बेस बेंगलुरु में स्थापित कर सकती है। वहीं से देश के अन्य शहरों के लिए हवाई संपर्क की सुविधा मुहैया कराएगी। कतर एयरवेज ने भारत में अपनी सहयोगी कंपनी के जरिये फुल सर्विस एयरलाइन शुरू करने की योजना बनाई है। फिलहाल केवल एयरएशिया इंडिया ही ऐसी कंपनी है, जिसने बेंगलुरु को अपना आधार बनाया है। यह कंपनी मलेशिया की एयर एशिया और टाटा संस का संयुक्त उद्यम है।

ऑनलाइन क्लेम सेटल करने के लिए आवेदन को पूरी तरह लागू कर चुका है। सप्लाई चेन का डिजिटाइजेशन होने से उसके मैटीरियल, फाइनेंस और सुचनाओं का आबाध आवागमन सुनिश्चित हो सकेगा। इससे रेलवे की कार्यकुशलता और उत्पादकता में सुधार होने की संभावना है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु 11 अप्रैल को डिजिटल कांट्रेन्ट को लांच करेंगे। डिजिटल कांट्रेन्ट समग्र डिजिटल सप्लाई चेन है। इस सप्लाई चेन से सभी पक्ष जैसे उद्योग, वित्तीय संस्थान, रेलवे के आंतरिक कस्टमर और निरीक्षण एजेंसियां जुड़ेंगी। इससे समूची चैन ज्यादा कार्यकुशल, जवाबदेह और पारदर्शी हो जाएगी।

नई दिल्ली, प्रे्ट : वीते चार साल से गोलड ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) की लेकर निवेशकों में मंदईया रूझान बना हुआ है। यही वजह है कि पिछले वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान भी उन्होंने गोलड लिंक्ड 14 ईटीएफ से 775 करोड़ रुपये की निकासी की। इसके चलते गोलड फंडों के एसेट अंडर मैनेजमेंट (एएएम) में 16 फीसद की कमी आई। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएफ्मी) की ओर से यह जानकारी दी गई है। गोलड ईटीएफ ऐसे निवेश इस्ट्रमेंट हैं जो सोने की कीमतों पर आधारित होते हैं। ये ईटीएफ सोने में निवेश करते हैं।

लगातार चार वर्षों से गोलड ईटीएफ सेगमेंट में कारोबार सुरूत दिख रहा है। इस दौरान वर्ष 2013-14 में निवेशकों ने 2,293 करोड़ रुपये की निकासी की। इसके अगले वर्ष उन्होंने ईटीएफ से 1,475 करोड़ रुपये निकाले। वर्ष 2015-16 में यह आंकड़ा 903 करोड़ रुपये रहा। अलबत्ता इन आंकड़ों से यह निकासी की रफ्तार में कमी आ रही है।

आधार आधारित सिस्टम की शुरुआत 14 बैंकों के साथ होने की संभावना है। इनमें से पांच बैंक भारतीय स्टेट बैंक, सिंडीकेट बैंक, आईडीएफसी बैंक, आंध्रा बैंक और इंडसइंड बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। सरकार ने आधार पे को भीम के साथ जोड़ने का इरादा जताया है। इससे सभी बैंक एक साथ नयी सुविधा मुहैया करा सकेंगे।

नीति आयोग को भी लेटलतीफी का रोग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मोदी सरकार ने योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग तो बना दिया लेकिन इसे भी अपने पूर्ववर्ती आयोग की तरह शायद लेटलतीफी का रोग लग गया है। हाल यह है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना खत्म होने के बावजूद नीति आयोग अब तक न तो इसकी मध्यावधि समीक्षा पेश कर पाया है और न ही पंचवर्षीय योजनाओं की जगह लागू होने वाली त्रिवर्षीय कार्ययोजना, 7 वर्षीय कार्यनीति और 15 वर्षीय विजन दस्तावेज का जगहा तैयार कर पाया है। शायद यही वजह है कि अब संसद सदस्य सरकार से पूछने लगें हैं कि नीति आयोग त्रिवर्षीय कार्ययोजना कब तैयार करेगा।

संसद के मौजूदा सत्र के दौरान वीते एक हफ्ते में लगातार दूसरी बार संसद सदस्यों के सवालों के जवाब में यह मुद्दा सामने आया है। पहला सवाल पांच अप्रैल को गोरखपुर से सांसद और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लोकसभा में पूछा गया था। उन्होंने योजना क्रियान्वयन मंत्री से पूछा था कि क्या सरकार ने त्रिवर्षीय कार्य योजना का प्रारूप तैयार किया है। इसके जवाब में योजना मंत्री ने



12वीं योजना पिछले मार्च में खत्म लेकिन त्रिवर्षीय योजना तैयार नहीं

सदन को बताया था कि त्रिवर्षीय कार्ययोजना के साथ-साथ सात वर्षीय कार्यनीति और 15 वर्ष के विजन दस्तावेज के लिए प्रारूप तैयार करने का कार्य उन्नत चरण में है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में वर्ष 2016 में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, सांपदकों, कृषि विशेषज्ञों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र तथा रक्षा व आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ छह विचार विमर्श बैठकें कीं।

इस तरह योजना क्रियान्वयन मंत्रालय ने

फ्लिपकार्ट ने जुटाए 90 अरब रुपये

माइक्रोसॉफ्ट, टेनसेंट व इबे ग्लोबल ने खरीदी हिस्सेदारी

नई दिल्ली, प्रे्ट/रायटर् : देश की दिग्गज ई-कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट ने तीन कंपनियों से 1.4 अरब डॉलर (करीब 9,050 करोड़ रुपये) की राशि जुटाई है। यह किसी भी भारतीय इंटरनेट कंपनी की ओर से जुटाई गई सबसे बड़ी राशि है। माइक्रोसॉफ्ट, टेनसेंट होल्डिंग्स (चीन की इंटरनेट सेवा कंपनी) और इबे ग्लोबल ने यह रकम उपलब्ध कराई है। फ्लिपकार्ट ने सोमवार को इस सौदे का एलान किया। इससे पहले भी फ्लिपकार्ट कई दौर में तीन अरब डॉलर (लगभग 19,365 करोड़ रुपये) जुटा चुकी है। इसमें ज्यादातर रकम टाइगर ग्लोबल, हसेले पार्टनर्स व डीएसटी ग्लोबल जैसे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से आई। फ्लिपकार्ट का मौजूदा वैल्युएशन 11.6 अरब डॉलर (करीब 74,800 करोड़ रुपये) है। वर्ष 2015 में कंपनी का बाजार मूल्य 15 अरब डॉलर (लगभग 96,825 करोड़ रुपये) आंका गया था।

यह घोषणा उस समय हुई है, जब कुछ महीने से भारतीय इंटरनेट कंपनियों के लिए फंडिंग के स्रोत सूखते नजर आ रहे थे। यही नहीं, फ्लिपकार्ट व स्नैपडील को अमेजन जैसी ग्लोबल ई-कॉमर्स दिग्गज की और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। अमेजन ने बीते साल भारत में पांच अरब डॉलर का निवेश करने का एलान किया था। फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल व बिनी बंसल ने कहा कि इस सौदे के जरिये भारत में तकनीकी की मदद से कारोबार को बढलने का भरोसा और मजबूत हुआ है। अमेजन में काम कर चुके सचिन और बिनी ने दस साल पहले फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी। स्नैपडील की प्रमोटर कंपनी जैस्पर इंफोटेक में जापानी कंपनी सबसे बड़ी शोयधाक है। अगर यह सौदा हुआ तो देश के ई-कॉमर्स क्षेत्र का सबसे बड़ा अधिग्रहण होगा।

फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण	
वी रीड	2010
चक्रपक	2011
लेट्स बाय डॉटकॉम	2012
मिंद्रा	2014
एनजीपे	2015
एड आइ क्वालिटी	2015
फोन पे	2016
जवांग डॉट कॉम	2016
इबे इंडिया	2017

फिराक में है। वह इसके लिए जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक के साथ बातचीत कर रही है। स्नैपडील की प्रमोटर कंपनी जैस्पर इंफोटेक में जापानी कंपनी सबसे बड़ी शोयधाक है। अगर यह सौदा हुआ तो देश के ई-कॉमर्स क्षेत्र का सबसे बड़ा अधिग्रहण होगा।



फ्लिपकार्ट में विलय होगा इबे इंडिया का

ग्लोबल कंपनी इबे फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी के बदले 50 करोड़ डॉलर (करीब 3,225 करोड़ रुपये) का नकद निवेश करेगी। कंपनी ने इबे इंडिया का कारोबार भी फ्लिपकार्ट को बेच दिया है। अब इबे इंडिया को फ्लिपकार्ट चलाएगी। इसके अलावा फ्लिपकार्ट ने इबे ग्लोबल से करार किया है। इसके तहत इबे के प्रोडक्ट भारत में आ सकेंगे। साथ ही, फ्लिपकार्ट के उत्पाद विवर के खरीदारों तक पहुंच सकेंगे। इस साल के अंत तक यह सौदा पूरा हो जाएगा। इसके बाद इबे अपने सक्रिय ग्राहक फ्लिपकार्ट की ट्रांसफर करेगी। अलबत्ता इबे डॉट इन का अलग फर्म के रूप में अस्तित्व बना रहेगा।

नई दिल्ली : टोडीसेंट ने रिलायंस जियो की 4जी सेवाओं के मामले में दायक याचिका पर सुनवाई टाल दी है। अब इस पर सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्रि ने रिलायंस जियो को पूर्व निर्धारित 90 दिनों की अवधि के बाद भी मुफ्त 4जी सेवाएं देने की अनुमति दी थी। इसके विरुद्ध एयरटेल और आइडिया ने अपील की थी। जियो ने पिछले साल सितंबर में प्री वॉइस व डाटा प्लान का मुफ्त ऑफर दिया था। दिसंबर में कंपनी ने यह ऑफर मार्च तक बढ़ा दिया। प्रतिस्पर्धी कंपनियों ने तीन महीने के आगे मुफ्त ऑफर को ट्राई द्वारा अनुमति दिये जाने को चुनौती दी है।

वोडाफोन के पत्र में कहा गया है कि उसकी गय में मानकों के विरुद्ध प्लान लेने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहन करना ट्राई के निर्देश का धोर उल्लंघन और अपमान है। इस तरह के प्रमोशन से प्लान वापस लेने की ट्राई की सलाह निरर्थक हो जाती है।

जियो के विरुद्ध टीडीसेंट में सुनवाई टली

नई दिल्ली : टोडीसेंट ने रिलायंस जियो की 4जी सेवाओं के मामले में दायक याचिका पर सुनवाई टाल दी है। अब इस पर सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्रि ने रिलायंस जियो को पूर्व निर्धारित 90 दिनों की अवधि के बाद भी मुफ्त 4जी सेवाएं देने की अनुमति दी थी। इसके विरुद्ध एयरटेल और आइडिया ने अपील की थी। जियो ने पिछले साल सितंबर में प्री वॉइस व डाटा प्लान का मुफ्त ऑफर दिया था। दिसंबर में कंपनी ने यह ऑफर मार्च तक बढ़ा दिया। प्रतिस्पर्धी कंपनियों ने तीन महीने के आगे मुफ्त ऑफर को ट्राई द्वारा अनुमति दिये जाने को चुनौती दी है।

वोडाफोन के पत्र में कहा गया है कि उसकी गय में मानकों के विरुद्ध प्लान लेने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहन करना ट्राई के निर्देश का धोर उल्लंघन और अपमान है। इस तरह के प्रमोशन से प्लान वापस लेने की ट्राई की सलाह निरर्थक हो जाती है।

गोल्ड ईटीएफ से निकासी जारी

नई दिल्ली, प्रे्ट : वीते चार साल से गोलड ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) की लेकर निवेशकों में मंदईया रूझान बना हुआ है। यही वजह है कि पिछले वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान भी उन्होंने गोलड लिंक्ड 14 ईटीएफ से 775 करोड़ रुपये की निकासी की। इसके चलते गोलड फंडों के एसेट अंडर मैनेजमेंट (एएएम) में 16 फीसद की कमी आई। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएफ्मी) की ओर से यह जानकारी दी गई है। गोलड ईटीएफ ऐसे निवेश इस्ट्रमेंट हैं जो सोने की कीमतों पर आधारित होते हैं। ये ईटीएफ सोने में निवेश करते हैं।

लगातार चार वर्षों से गोलड ईटीएफ सेगमेंट में कारोबार सुरूत दिख रहा है। इस दौरान वर्ष 2013-14 में निवेशकों ने 2,293 करोड़ रुपये की निकासी की। इसके अगले वर्ष उन्होंने ईटीएफ से 1,475 करोड़ रुपये निकाले। वर्ष 2015-16 में यह आंकड़ा 903 करोड़ रुपये रहा। अलबत्ता इन आंकड़ों से यह निकासी की रफ्तार में कमी आ रही है।

नीति आर

सीधे-सीधे यह कहने के बजाय कि अब तक कार्ययोजना तैयार नहीं हुई है, इसका गोलमोल जवाब दिया।

इधर राज्यसभा में भी सोमवार को एक सवाल के लिखित जवाब में योजना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह ने वही जवाब दोहरा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार त्रिवर्षीय कार्ययोजना, सात वर्षीय कार्यनीति और 15 वर्षीय विजन दस्तावेज तैयार कर रही है।

उल्लेखनीय है कि नीति आयोग ने 1950 से चली आ रही पंचवर्षीय योजनाएं बनाने की परंपरा को खत्म कर त्रिवर्षीय कार्ययोजना बनाने का एलान किया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च, 2017 को खत्म हो चुकी है। लेकिन आयोग अपने दो साल के कार्यकाल में अब तक इसकी मध्यावधि समीक्षा भी देश के समक्ष पेश नहीं कर पाया है।

योजना आयोग के समय अक्सर पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने में विलंब होता था लेकिन नीति आयोग बनने के बावजूद अब तक देश के विकास की अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार नहीं हुई हैं। इससे लगता है कि विलंब की समस्या दूर नहीं हुई है।

सापे पछ) हो। समीपाइनलन में पहुँचने वाला लाटाई फनल ही क्वालीफाई कर लेता, जबकि लाटाई फनलन में हारने वाले खिलाड़ियों को चार बायस ऑफ से पांचवें और छठे स्थान का इशारा किया जाएगा। भारत ने 2015 में पिछली एशियाई चैंपियनशिप में चार पदक जीता था। कास ने देश के लिए एकमात्र रजत पदक जीता जबकि शिव, देवेंद्र और सतीश कुमार (91 किग्रा से अधिक) ने कांस्य पदक जीते थे। सतीश आगामी चैंपियनशिप के लिए भी चुना गया है। शिव के लिए एशियाई चैंपियनशिप में पिछला स्वर्ण पदक शिव थापे ने 2013 में जीता था। तब उन्होंने 100 किलो वर्ग में खिलवा जीता था। इससे पहले पुष्पराज शर्मा (52 किग्रा) ने 2009 में स्वर्ण पदक जीतने का सपना साकार किया था।



1919 में आज ही दुनियाभर के श्रमिकों की समस्याएं दूर करने और उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। 187 देश इसके सदस्य हैं। श्रमिकों के उत्थान के लिए कार्यरत इस संगठन को 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

इधर उधर की

दोस्ती के चक्कर में पड़ गए लेने के देने

लंदन, एप्रैली : अक्सर दोस्त एक दूसरे की सहायता करते हैं। मुश्किल वक़्त में साथ निभाते हैं। लेकिन यहां एक महिला को दोस्ती निभाने के चक्कर में कोर्ट जाना पड़ गया। दरअसल पेरों से आर्किटेक्ट बेसिया लेजोनवार्न की सहेली लिन को घर में खूबसूरत बगीचा तैयार करवाना था। लिन ने कई जाने-माने आर्किटेक्ट से बात की लेकिन उनकी फीस इतनी अधिक थी कि वह मन मारकर रह गई। ऐसे में बेसिया अपनी दोस्त की मदद करने आगे आईं। उन्होंने सस्ते दामों पर लोगों को नियुक्त किया और बगीचा तैयार करवाया। बेसिया ने खुद अपनी फीस तक नहीं ली। जब बगीचा बन गया तो लिन को वह पसंद नहीं आया। उसने बेसिया पर 2.12 करोड़ रुपये का हर्जाना लगा दिया।

शोध अनुसंधान

खाली पेट व्यायाम करना ज्यादा



व्यायाम यूं तो शरीर को फायदा देता ही है, लेकिन खाली पेट व्यायाम करना और भी लाभकारी हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि खाली पेट व्यायाम करना आगे चलकर बहुत फायदा करता है। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का उतारो भी खोज निकाला है। शोध के दौरान नाश्ता करने के कुछ देर बाद और खाली पेट व्यायाम से वसा ऊतकों पर पड़ने वाले प्रभाव को जांचा गया। ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता डिलन थॉम्पसन ने कहा, 'नाश्ता करने के बाद वसा ऊतक खाने को पचाने में व्यस्त होते हैं। इस वक़्त व्यायाम का इन उतारों पर पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं, खाली पेट व्यायाम करने पर ये उतारों ज्यादा सक्रियता से व्यायाम पर प्रतिक्रिया देते हैं। यह सक्रियता भविष्य के लिहाज से बहुत फायदेमंद है।' यह इस तरह का पहला शोध है जिसमें व्यायाम से पहले नाश्ता करने के नुकसान पर अध्ययन किया गया है।

—आइएएनएस

अल्जाइमर की दवा से निमोनिया का खतरा



बड़ी उम्र में होने वाली दिमागी बीमारी अल्जाइमर के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाओं का दुष्प्रभाव सामने आया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन दवाओं के प्रयोग से मरीज को निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। अल्जाइमर में व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अल्जाइमर के मरीजों को बेंजोडायजेपाईस और नॉन बेंजोडायजेपाईस दवाएं दी जाती हैं। इन दवाओं से निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड के शोधकर्ता हेदी ताइपल ने कहा, 'निमोनिया का खतरा बढ़ने संबंधी यह शोध अल्जाइमर के मरीजों के इलाज की दिशा में व्यापक बदलाव लाएगा। निमोनिया के कारण अल्जाइमर के मरीजों की मौत के कई मामले सामने आते हैं।' शोधकर्ताओं ने बताया कि इन दवाओं के प्रयोग से निमोनिया का खतरा 30 फीसद तक बढ़ जाता है। इलाज के पहले नहीं में यह खतरा सबसे ज्यादा रहता है।

—आइएएनएस

संरक्षण का प्रयास

देवभूमि उत्तराखंड वनसंपदा का धनी राज्य है। वन्य जीवों की भी बहुतायत है। तमाम प्रयासों के बावजूद वनों और वहां निवास करने वाले जीवों की स्थिति अच्छी नहीं है। मृग (हिरन) तो विलुप्तप्राय क्षेणी में पहुंच गए हैं।

कस्तूरी मृगों के लिए तलाश रहे नया ठौर

किशोर जोशी, नैनीताल

छह दशक से बागेश्वर जिले के धरमघर स्थित फार्म की शान रहे कस्तूरी मृगों के लिए अब नए आशियाने की तलाश की जा रही है। इसे लेकर केंद्रीय आयुष मंत्रालय और राज्य सरकार में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। बहुत संभव है कि कस्तूरी मृगों का अमला बसेश नैनीताल का चिड़ियाघर हो। वर्तमान में कस्तूरी फार्म में विलुप्तप्रायः श्रेणी में शुमार 20 मृग (हिरन) वास कर रहे हैं।

कस्तूरी से परस्पृश (इत्र) व दवा बनाने के मकसद से 60 के दशक में इस फार्म की स्थापना की गई थी। आयुष विभाग को इसके संचालन का जिम्मा सौंपा गया। तब कस्तूरी मृगों की संख्या बहुतायत में होने के चलते विभाग के लिए यह आव का जरिया बना, लेकिन धीरे-धीरे कस्तूरी मृगों की संख्या में कमी आती गई। अब फार्म में इनकी संख्या सिर्फ 20 ही रह गई है। समुद्र तल से ढाई पांच हजार मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाने वाले कस्तूरी मृगों की संख्या में गिरावट के मददेनजर केंद्र सरकार ने इसे विलुप्तप्रायः श्रेणी यानी शोड्यूल-एक में शुमार कर दिया। साथ ही इनके संरक्षण के नियमों में आमूलचूल परिवर्तन



धरमघर बागेश्वर के फार्म में विचरण करता कस्तूरी मृग।

कर दिया। इसके चलते आयुष विभाग के हाथ भी बंध गए। फार्म में पल रहे मृगों से कस्तूरी निकालना उसके अधिकतम क्षेत्र में नहीं रह गया। वर्तमान में यहां रह रहे कस्तूरी मृगों की देखभाल आयुष विभाग जरूर कर रहा है, लेकिन अब उसकी व्यावसायिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसी को देखते हुए इन मृगों का आशियाना बदलने की योजना पर काम चल रहा है।

ज्ञात हो, कस्तूरी मृग समुद्र तल से ढाई से पांच हजार मीटर ऊंचाई वाले स्थानों में पाया जाता है। उत्तराखंड के अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) डॉ. धनंजय मोहन ने बताया कि कस्तूरी मृग फार्म आयुष विभाग से वन विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद तब किया जाएगा कि मृगों को कहाँ शिफ्ट किया जाए।

जागरण

ब्रिटेन से चीन के लिए पहली मालगाड़ी रवाना

सात देशों से होकर गुजरेगी



लंदन, आइएएनएस : ब्रिटेन के एसेक्स से चीन के लिए पहली मालगाड़ी सोमवार को रवाना हुई। यह ट्रेन लगभग 7500 मील की दूरी करीब 18 दिन में तय करके चीन पहुंचेगी। समाचार एजेंसी बीबीसी के अनुसार, मालगाड़ी पर लंदे 30 कंटेनरों में द्रिक्स, साफ्ट ड्रिंक, विटामिन और दवाएं रखी गई हैं। यह ट्रेन स्टैनफोर्ड-ली-होप के लंदन गेटवे रेल टर्मिनल से झेजियांग प्रांत के यिवू शहर के लिए रवाना हुई है। मालगाड़ी सात देशों फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, रूस और कजाखिस्तान होते हुए 27 अप्रैल को गंतव्य को

तक पहुंचेगी। यह सेवा चीन के प्राचीन सिल्क रूट को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। तकरीबन 2000 साल पहले सिल्क रूट के जरिये पश्चिम और पूर्व के बीच कारोबार होता था। वामपंथी देश चीन ने इस मार्ग की शुरुआत के तौर पर तीन महीने पहले ब्रिटेन के लिए एक मालगाड़ी भेजी थी। इसमें घरेलू जरूरतों का सामान, कपड़े, सूटकेस और बैग आदि थे। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री ग्रेग हैंड ने कहा कि एशिया की महाशक्ति चीन के साथ यह नया रेल लिंक ब्रिटेन के वैश्विक उद्देश्यों को बढ़ावा देने वाला है।

सार्थक पहल ▶ मच्छरों के पनपने का पहले ही मिलेगा पता

चिकनगुनिया से लड़ाई में साथ देगा मौसम विभाग

चिकनगुनिया और डेंगू के मच्छरों के पनपने में नमीयुक्त एक खास वातावरण होता है असरदार संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

साल दर साल दिल्ली-एनसीआर में महामारी का रूप लेते जा रहे डेंगू एवं चिकनगुनिया की रोकथाम में मौसम विभाग भी अब एक अहम भूमिका अदा करेगा। विभागीय स्तर पर नमी एवं तापमान वाले उस वातावरण का पूर्वानुमान पहले ही दिल्ली सरकार व नगर निगम को बता दिया जाएगा जिसमें इन बीमारियों के जनक मच्छर पैदा होते हैं। देश के अन्य हिस्सों की तरह ही राजधानी में भी मानसून के दौरान हर जगह लापरवाही का नजारा देखने को मिलता है। जगह-जगह जल भराव तो होता ही है, जल जनित रोगों और मच्छरों की उत्पत्ति रोक्ने के लिए भी पुख्ता प्रयास नहीं किए जाते। यही वजह है कि हर

हमने डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए भी योजना तैयार की है, लेकिन सकारात्मक परिणाम के लिए ईमानदार प्रयास बहुत जरूरी है। हम तो संबंधित विभागों को हप्ते-दस दिन का सटीक पूर्वानुमान ही दे सकते हैं। उसके अनुरूप काम स्थानीय निकायों और सरकारी विभागों को करना होगा।

—डा. के.जे. रमेश, महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग

साल चिकनगुनिया व डेंगू बड़े पैमाने पर दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को अपना शिकार बना लेता है।

मौसम विभाग की यह योजना ईमेल पर क्रियान्वित होगी। मौसम विज्ञानी दिल्ली सरकार, आपदा प्रबंधन और तीनों नगर निगमों के आला अधिकारियों को जून माह से हर सप्ताह ईमेल भेजना शुरू करेंगे। इस ईमेल में मौसम विज्ञानी अगले एक सप्ताह के लिए पूर्वानुमान देंगे कि उस सप्ताह में बारिश कहाँ और कितनी रहेगी, तापमान कितना रहेगा और नमी कितने फीसद

तक रहने की संभावना है। पूर्वानुमान के साथ-साथ यह भी बताया जाएगा कि चिकनगुनिया एवं डेंगू का प्रकोप ज्यादा न फैले, इसके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं।

इस पूर्व सूचना के आधार पर दिल्ली सरकार और नगर निगम के अधिकारी जल भराव से निपटने और दवा का छिड़काव करने की दिशा में पूरी तैयारी कर सकेंगे। यही नहीं, डिस्पेंसरियाँ एवं अस्पतालों की भी समय पूर्व अलर्ट किया जा सकेगा। विभाग की ओर से इस आशय की विभागीय बैठक भी हो चुकी है और मौसम विज्ञानी एससी भान को नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जा चुका है।

70 से 90 फीसद नमी में पनपता है डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर : मानसून के दौरान ही चिकनगुनिया और डेंगू का जनक मादा एडीज एजेटाइज मच्छर पैदा होता है। चिकित्सकों और अन्य विज्ञानियों का कहना है कि चिकनगुनिया और डेंगू फैलाने वाले इस मच्छर की उत्पत्ति में 22 से 31 डिग्री सेल्सियस तापमान और 70 से 90 फीसद की नमी खासी मददगार साबित होती है।



झारखंड में 'बेगम जान' टैक्स फ्री

बंगाली फिल्मकार श्रीजित मुखर्जी की 'बेगम जान' की रिलीज अब महज तीन दिन दूर है। इतफाकत झारखंड सरकार ने उसे कर मुक्त कर दिया है। साथ ही फिल्म को दो करोड़ रुपये की सॉफ्टडी भी मिली है। ऐसा वहां की फिल्म नीति के प्रावधानों के तहत किया गया है। विद्या बालन इसमें अलग ही अवतार में हैं। इसकी कलनी विभाजन काल में सेट है। विद्या के किर्दार का नाम बेगम जान है। वह कोटा चलाती है। विभाजन बाद रेडिकलफ लाइन खींचने के चलते उसका कोटा खारे में आ जाता है। तब वह क्या कुछ करती है, फिल्म उस बारे में है। यह फिल्म पूरी तरह से झारखंड में शूट हुई है। निर्माता

विशेष भट्ट ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'झारखंड कमाल का मेजबान है। सरकार के इस कदम के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इससे हमारी फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। फिल्म में इला अर्पण, गौहर खान, रजित कपूर, आशीष विद्यार्थी, चंकी पांडे, विवेक मुश्रान, रिद्धिमा तिवारी, पल्लोरा सेनी, प्रियंका सेंटिया, रविजा चौहान, मिट्टी चक्रवर्ती, पूनम सिंह राजपूत, सुमित निज़ाम, पितोबास और राजेश शर्मा में भी हैं। नसीरुद्दीन शाह का फिल्म में स्पेशल एपीरियंस है। इसे मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट और प्ले एंटरटेनमेंट ने मिलकर प्रोड्यूस किया है।

सौर ऊर्जा को कैद करने की नई विधि खोजी

वाशिंगटन, प्रे्ट : पृथ्वी पर सूरज का इतना प्रकाश पहुंचता है कि उससे कई बार दुनिया की ऊर्जा जरूरतें पूरी की जा सकती हैं लेकिन इस ऊर्जा को कैद करना बहुत मुश्किल है। 2013 तक विश्व की सिर्फ एक फीसद बिजली ही सौर पैनलों से प्राप्त हुई थी। पारंपरिक सौर सेलों की कार्यकुशलता ज्यादा से ज्यादा एक-तिहाई तक ही होती है। सौर सेलों की इस सीमा को वैज्ञानिक शोक्ली-क्वजर सीमा कहते हैं। सौर सेल सेमीकंडक्टर के रूप में सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इससे सिर्फ एक-तिहाई बिजली ही स्रपित हो पाती है। शोधकर्ताओं ने अब आयोडीन, सीसे और मिथाइल एमोनियम से ऐसा पदार्थ बनाया है जो सिलिकॉन का स्थान ले सकता है। और सौर सेलों की कार्यकुशलता को दोगुना कर सकता है। नए पदार्थ की पहचान अमेरिका में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी और नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लैबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने की है। पर्ड्यू में सत्यनाशस्त्र के प्रोफेसर लिबाई हुआंग का कहना है कि नए पदार्थ से बनने वाले सोलर सेल पारंपरिक सोलर सेलों की तुलना में बहुत पतले, लचीले और सस्ते होंगे और इन्हें बनाना भी आसान होगा।



चीन में बहनों का पर्व

चीन के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत गुइज़हौ की तियाजियांग काउंटी में प्रतिवर्ष सिस्टर फेस्टिवल पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। खासतौर पर मियाओ आदिवासी समुदाय की युवतियां पारंपरिक कोंस्ट्यूम पहनकर परेड में शामिल होती हैं। तीसरे चंद्र माह के 15 वें दिन आयोजित यह महोत्सव मियाओ समुदाय के सबसे प्रमुख पर्व में से एक है। इस मौके पर युवतियां अपने लिए योग्य जीवन साथी का चुनाव भी करती हैं। इस दौरान लोग विशेष रूप से तैयार सिस्टर राइस खाते हैं। इसके अलावा युवतियां ड्रेस परेड, डांस, बुल फाइटिंग और गाने के कार्यक्रमों का लुत्फ उठाती हैं।

एएफपी

ब्लीचिंग से तबाही के कगार पर ग्रेट बैरियर रीफ

केनबरा, आइएएनएस : यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल दुनिया की सबसे बड़ी मृगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ को ब्लीचिंग से जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया स्थित इस मृगे की चट्टान का करीब 1,500 किमी क्षेत्र यानी दो तिहाई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। एक के बाद एक लगातार दो साल ब्लीचिंग की घटना ने इस क्षेत्र को तबाही के कगार पर ला दिया है।

ऑस्ट्रेलिया की जेम्स कुक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टेरी ह्यूस ने बताया कि अब केवल दक्षिण का एक तिहाई हिस्सा ब्लीचिंग से सुरक्षित है। 2016 में तापमान में वृद्धि और अल नीनो प्रभाव के कारण उत्तरी एक तिहाई हिस्सा प्रभावित हुआ था। उसके बाद साल भर से कम समय में ही मध्य का तिहाई हिस्सा इसकी चपेट में आ गया है। टेरी ने बताया कि इस साल अल नीनो के बिना ही व्यापक ब्लीचिंग देखने को मिल रही है। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में व्यापक भूधन पुनान ने भी ग्रेट बैरियर रीफ को व्यापक नुकसान पहुंचाया। तापमान में वृद्धि के कारण पानी गर्म होने पर ब्लीचिंग की घटना होती है। इसमें मृगा शेवाल को खुद से अलग कर देता है। इसके कारण वह सख्त और सफेद हो जाता है। इन परिस्थितियों में उसका क्षय शुरू हो जाता है। मामूली नुकसान होने पर तापमान में गिरावट होते ही मृगा सामान्य अवस्था में आ जाता है, लेकिन व्यापक ब्लीचिंग होने से इसका मूल अवस्था में लौटना मुश्किल हो जाता है।

कैमरा रखेगा नवजात की धड़कनों पर नजर

जेनेवा, प्रे्ट : वैज्ञानिकों ने समय पूर्व प्रसव से जन्मे बच्चों की सेहत पर नजर रखने का आसान तरीका खोज निकाला है। वैज्ञानिकों ने ऐसा कैमरा बनाया है जो बच्चे को स्पर्श किए बिना ही उसकी धड़कन और सांस की गति को मापने में सक्षम होगा। अभी बच्चों के सीने पर सेंसर लगाकर यह जानकारी हासिल की जाती है।

कैमरे को स्विट्जरलैंड के लोसाने स्थित ईपीएफएल पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी और स्विस् सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। अभी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ज्यूरिख (यूएसजेड) में इसका परीक्षण किया जाना है। यूएसजेड के डॉ. जीन क्लाउडे फॉर्शर ने कहा, 'बच्चों के सीने पर लगाए जाने वाले सेंसर बेहद संवेदनशील होते हैं।

इनका अलार्म 90 फीसद तक गलत समय पर बज जाता है। यह बच्चों के लिए असुविधाजनक होता है, क्योंकि हर अलार्म पर चिकित्सक उनकी जांच करते हैं। साथ ही वहां कार्यरत नर्स और चिकित्सक के समय को भी बर्बाद होती है।' नए कैमरे से यह समस्या दूर हो सकती है। यह बच्चे की त्वचा के रंग में होने वाले बदलाव की मदद से उसकी धड़कन का पता लगाता है। सांस का पता उसकी सीने और कंधों में होती हलचल से चलता है। रात में वह कैमरा इंग्रॉइड शैशनी की मदद से काम करता है।

आपको सेहतमंद रखेगा फसलों का नया बीज

जागरण संवाददाता, बरेली

फसल में अत्याधिक उर्वरक के प्रयोग से खाद्यान्न भी सेहत को क्षति पहुंचा रहे हैं लेकिन अब नए बीज से उत्पादित खाद्यान्न सेहतमंद करेगा। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित यह बीज जल्द किसानों तक पहुंचाया जाएगा।

कृषि मंत्रालय के महानिदेशक प्रो.त्रिलोचन महापात्रा ने मुताबिक, भारत में जापान-अमेरिका आदि देशों की अपेक्षा उर्वरक का प्रयोग कम है लेकिन किसानों को इस्तेमाल करने की जानकारी नहीं। इसलिए फसल में जरूरत से ज्यादा प्रयोग करते हैं। नए बीज से उत्पादित खाद्यान्न में उर्वरक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल का पौधा बढ़ेगा लेकिन खाद्यान्न पर कोई असर नहीं होगा। नए बीज में जिंक, प्रोटीन समेत सभी पोषक तत्व होंगे, जो इसान की सेहत के लिए काफी फायदेमंद हैं। इन पोषक तत्वों की कमी से

जैविक खेती से बढ़ेगा मुनाफा

कुछ साल जैविक खेती में किसानों को नुकसान होने की बात सामने आई है। पौधों को जैविक खाद की ज्यादा जरूरत होती है, मगर अब शोध चल रहा है। इससे कम जैविक खाद भी पौधे को ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। इससे जैविक खेती करने वालों का मुनाफा बढ़ेगा।

ही महिलाओं और पुरुषों में तमाम बीमारियां फैल रही हैं। महानिदेशक ने बताया, चीनी उत्पादन बढ़ाने के लिए गन्ने के सीओ-238 बीज विकसित किया गया है। नए बीज से 12 फीसद तक चीनी की रिकवरी मिलेगी। बोले, फसल उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। इसलिए नए बीज की फसल में उत्पादन पहले से ज्यादा होगा।

यमुना में उगा दीं गेहूं की लंबी बालियां

यमुनानगर : यमुना की जिस रेतीली धरा से किसान किनारा कर लेते हैं, उसी जमीन पर 73 साल के कनालसी निवासी रूढ़ सिंह ने गेहूं की 18 से 19 सेंटीमीटर की बालियां उगा दी हैं। उसकी फसल को देख न केवल आसपास की किसान बल्कि कृषि विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं। किसान का कहना है कि एक गेहूं की बाली में 100 से अधिक दाने हैं।

कनालसी निवासी रूढ़ सिंह ने बताया कि 1987 में उन्होंने सहकारिता विभाग से ऑडिटर की नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी कि वह खेती को प्रोत्साहन दे सकें। उन्होंने बताया कि यमुना नदी के किनारे उनकी करीब 40 एकड़ जमीन है। यह रेतीली है। इस दौरान उन्होंने 411 किस्म की गेहूं के बारे में सुना था।

स्क्रीन शॉट

‘तुम्हारी सुलू’ में आरजे होंगी विद्या बालन

पिछले कुछ अर्से से विद्या बालन संजीदा किरदारों में नजर आ रही हैं। 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली 'बेगम जान' में वह कोटे



की होस्ट होंगी। यहां पर वह लव गुरु सरीखी भूमिका में होंगी। विद्या के मुताबिक सुलू की भूमिका में उनका नटखट अंदाज दिखेगा। फिल्म में उनके पति की भूमिका में मानव कौल होंगे। वह 'सिटी लाइट', 'काय पो छे', 'जय गंगाजल', 'मेरून' जैसी फिल्मों में अहम भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म का निर्देशन सुरेश दिवेणी ने किया है। फिल्म एक दिसंबर को रिलीज होगी।

मुंबई ब्यूरो

‘सैराट’ के अभिनेता का बढ़ा रहे हौसला



है। सलमान ने मराठी फिल्म 'सैराट' के अभिनेता आकाश ठोसर की आने वाली फिल्म 'फू' का पोस्टर जारी कर उनका उत्साहवर्धन किया है। सलमान ने ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'सैराट अभिनेता आकाश ठोसर, महेश मांजरेकर के साथ पढ़े पर वापसी कर रहे हैं। अभिनेता ने निर्देशक नागराज मंजुले की मराठी फिल्म 'सैराट' से अभिनय जगत में अपना पहला कदम रखा था। फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई थी। उल्लेखनीय है कि फिल्म का निर्देशन सलमान के दोस्त एवं फिल्मकार महेश मांजरेकर ने किया है। 'फू' दो जून को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। आकाश की यह दूसरी फिल्म होगी। —प्रेट

जया के बर्थडे पर अभिषेक का खास तोहफा

अभिषेक बच्चन ने अपनी मां जया बच्चन के जन्मदिन पर उन्हें खास तोहफा दिया। अभिषेक ने सोशल मीडिया पर जया बच्चन की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए उनके नाम एक प्यारा-सा संदेश भी लिखा। अभिषेक ने सोशल मीडिया के जरिये उनकी काफी पुरानी तस्वीर साझा करते हुए लिखा- 'हैप्पी बर्थडे मां, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या लिखता हूं, मैं कभी नहीं बता सकता कि आप मेरे लिए क्या



महत्व रखती हैं, आई लव यू।' अभिषेक की ओर से जारी की गई जया बच्चन की तस्वीर काफी पुरानी है। वह इस तस्वीर में बहुत कम उम्र की और प्यारी दिख रही हैं। उल्लेखनीय है कि जया बच्चन इस वर्ष 69 वर्ष की हो गई हैं। बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्रियों में शुमार जया बच्चन ने फिल्म 'गुड्डू' से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर कई सुपरहिट फिल्मों दी हैं। —मिड-डे